रायपुर, वर्ष-18, अंक- 5, मई 2022, मूल्य ₹ 10

दीप कमल

Front page

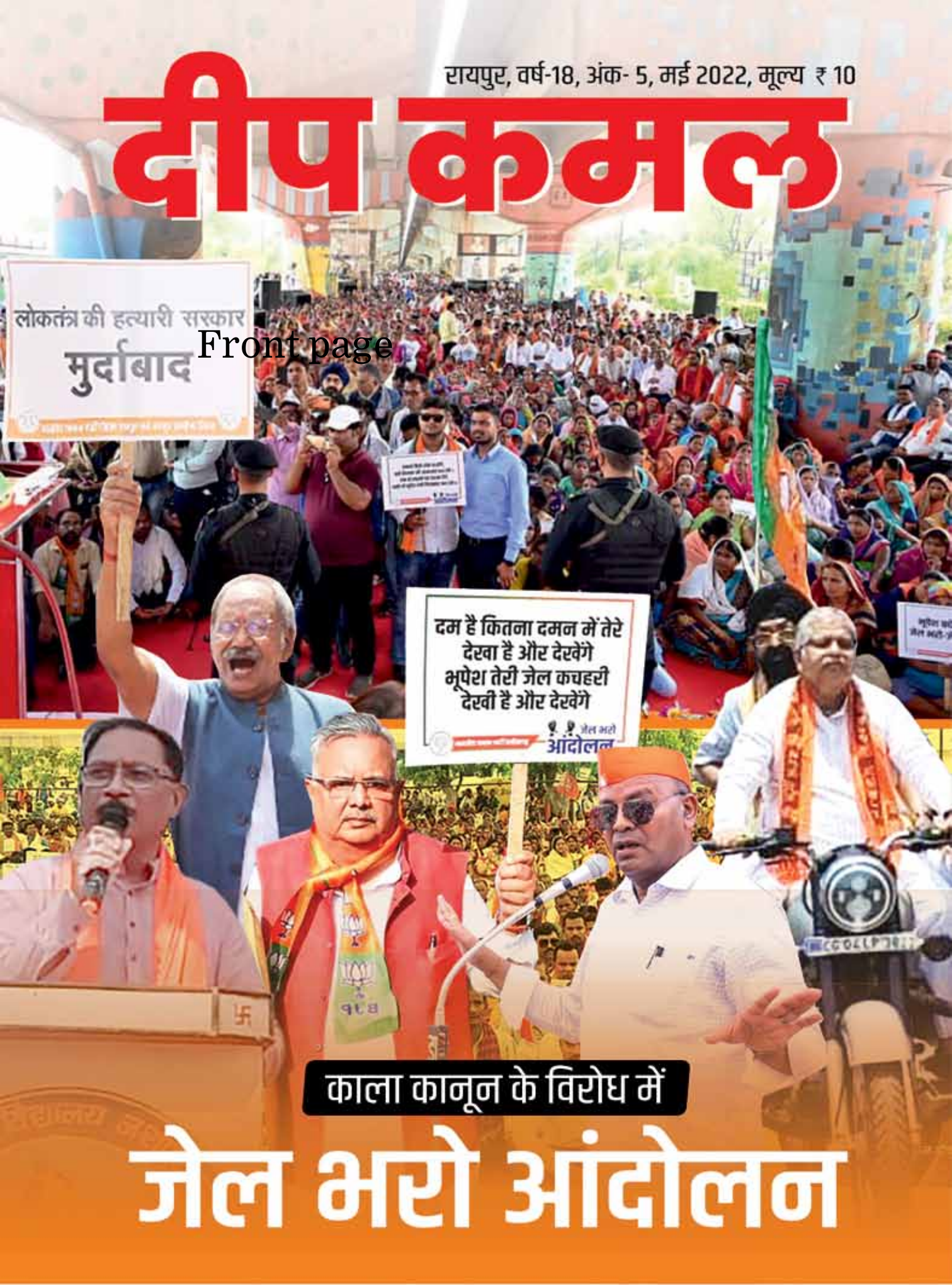

काला कानून के विरोध में

जेल भरो आंदोलन

दीप कमल

संपादक
सुभाष राव

कार्यकारी संपादक
पंकज कुमार झा

मुद्रक एवं प्रकाशक **विष्णुदेव साय** द्वारा, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़, के लिए **मूणत ऑफसेट प्रिंटर्स** रायपुर से मुद्रित एवं एकात्म परिसर, रजबंधा मैदान रायपुर से प्रकाशित।

स्वत्वाधिकारी
भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़

ई-मेल
jay7feb@gmail.com

फोन
0771-2233500, 4266000

सोशल मीडिया से

अंदर के पन्नों में

संगठन शिल्पी, राजनीति के कबीर ठाकरे जी 05
आत्मनिर्भर रहे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने बनाया कर्जदार 11
लोकतंत्र बचाने छत्तीसगढ़ में भाजपा सड़क पर 14
प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता देश के सपनों के प्रतिनिधि 16
देश भर में मना सामाजिक न्याय पखवाड़ा 18
खैरागढ़ का जनादेश विनम्रतापूर्वक स्वीकार 22
छत्तीसगढ़ को बार में बदल दिया कांग्रेस ने 24
एक अघोषित आपातकाल से गुजरता छत्तीसगढ़ 28

दूसरे आपातकाल की तैयारी में कांग्रेस!

अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की एक काफी प्रसिद्ध उक्ति है। लिंकन ने कहा था- 'आप कुछ लोगों को हमेशा बेवकूफ बना सकते हैं। सभी लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सभी लोगों को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते।' जनाक्रोश के आतंक को समझने के बाद समय से पहले शासकीय संसाधनों का बेदर्दी से दोहन करते हुए चुनावी यात्रा पर निकले सीएम बघेल के लिए भी यह उक्ति पूरी तरह चरितार्थ हो रहा है। या यूं कहें कि समूची कांग्रेस पर ही यह कथन सटीक बैठता है। वास्तव में अपनी स्थापना से लेकर आज तक कांग्रेस ने लोगों को ठगने के सिवा कुछ किया ही नहीं है। अब समय आ गया है कि सभी लोगों को हमेशा के लिए ठगने की कांग्रेसी कोशिश के खिलाफ छत्तीसगढ़ उठ खड़ा हो।

जैसा कि हम सब जानते हैं, राजनीतिक इतिहास की दुर्दांत ठगी में से एक दस्तावेज जिसे कांग्रेस ने 'जन घोषणा पत्र' का नाम दिया था, की कलई अब खुल गयी है। छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लोग अब साढ़े तीन वर्ष के बाद ही खुद को छला और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। खुद बघेल की भी यही चिंता है कि चावल का कटोरा कहे जाने वाले इस पुण्य भूमि पर उन्होंने अपनी काठ की हांडी एक बार तो चढ़ा ली, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि ऐसी हांडी दुबारा चढ़ती नहीं। इसी चिंता में बौखलाए फिर रहे बघेल अब जनता के साथ भी सामान्य शिष्टाचार तक का पालन नहीं कर पा रहे हैं। अनेक जगह सभाओं में ऐसा लग रहा मानो कोई मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक आदतन अपराधी जनता को हड़का रहा हो।

कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदेश के हर वर्ग में फैले ऐसे आक्रोशों का प्रकटीकरण छत्तीसगढ़ के दर्जनों संगठन लगातार सड़क पर कर रहे हैं। ऐसा आन्दोलन करना उन सभी संगठनों का बाबा साहेब द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार भी है। लेकिन असहमति और आक्रोश के उन स्वरों का सम्मान कर मांगों का निराकरण करने के बजाय बघेल ने प्रदेश भर में आंदोलनों पर एक तरह से प्रतिबन्ध जैसा ही लगा दिया है। चंगेज और अंग्रेज़ की तरह ही कांग्रेस अपना इतिहास दुहराते हुए छत्तीसगढ़ में एक नए तरह का आपातकाल लाने की कोशिश में दिख रही है। कांग्रेस सरकार ने धार्मिक-राजनीतिक-सामाजिक और जन संगठनों के आंदोलनों पर जिस तरह तुगलकी शर्त थोपे हैं, वैसे में कोई भी रैली-प्रदर्शन या आयोजन आदि कांग्रेस के रहमोकरम पर ही होना संभव होगा। संबंधित असंवैधानिक आदेश से प्राप्त ताकत का उपयोग कर कांग्रेस असहमति और विरोध की हर आवाज़ को कुचलने उसी तरह पिल पड़ेगी जैसे आपातकाल लगा कर राष्ट्रवादियों समेत सभी सज्जन शक्तियों को कुचला था। ज़ाहिर है, भारत का सशक्त लोकतंत्र देश के संविधान पर हो रहे ऐसे आक्रमण को किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेगा।

समाज के सभी वर्गों और संगठनों को साथ लेकर प्रदेश भर में भाजपा इस तुगलकी फरमान के खिलाफ कमर कस कर खड़ी हो गयी है। वह एक बार फिर से तीसरी आज़ादी की इस लड़ाई के लिए तैयार है। पार्टी ने शासन को स्पष्ट तौर पर चेतावनी देते हुए कांग्रेस सरकार से इस आततायी फैसले को वापस लेने कहा। लेकिन कांग्रेस को अपने भीतर लोकतंत्र की तमीज लाते हुए अपना फरमान वापस लेना था, लेकिन वह अपने अड़ियल रुख पर अड़ी रही।

ऐसे में अपने लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा में भाजपा ने प्रदेशव्यापी 'जेल भरो आन्दोलन' की। प्रदेश भर में एक लाख के करीब भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसमें सहभागी बन कर ऐतिहासिक एकजुटता का प्रदर्शन किया, आन्दोलन शानदार और ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। पार्टी के इस आंदोलन से यह तो तय है कि लाख सर पटक लें भूपेश लेकिन प्रदेश की जनता उनके अधिनायकवादी मंसूबे को अब पूरे नहीं होने देगी। यह एलन ओक्टावियो ह्यूम का ज़माना नहीं जब कांग्रेस अपने फिरंगी आकाओं को स्थापित रखने लोगों को बरगला लेती थी। यह नया भारत है जहां भाजपा छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की पुनर्बहाली के लिए, छत्तीसगढ़ महतारी के सम्मान बहाली के लिए एक बार फिर से कमर कस चुकी है। कांगेस जितना शीघ्र लोकतंत्र के प्रति सहिष्णु और तमीजदार बने, उतना ही उसकी सेहत अच्छी रहेगी, वरना समूचे देश की तरह ही छत्तीसगढ़ में भी उसका कोई नामलेवा नहीं बचेगा। भाजपा का यह आंदोलन कड़े शब्दों में यह सन्देश देने में पूरी तरह सफल रहा है। सभी भाजपा जनों को अशेष शुभकामना...बधाई और अभिनन्दन!

प्रतिक्रिया कृपया इस आईडी पर दें-

jay7feb@gmail.com

संगठन शिल्पी, राजनीति के कबीर स्व. कुशाभाऊ ठाकरे

विष्णुदेव साय

भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन शिल्पी कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्मशती समारोह मना रही है। स्व. ठाकरे का जन्म 15 अगस्त 1922 को मध्य प्रदेश के धार में हुआ था। उनकी शिक्षा ग्वालियर और धार में हुई। उनके पिता का नाम डॉ. सुन्दर राव श्रीपति राव ठाकरे और माता का नाम स्व. शांताबाइ सुंदर राव ठाकरे है। अविभाजित मध्य प्रदेश में विशेषत: संगठन को गढ़ने वाले ठाकरे जी सन 1942 से संघ के स्वयंसेवक रहे।

ठाकरे जी ने 1942 में नीमच से प्रचारक के दायित्व के साथ अपनी संगठन यात्रा प्रारम्भ की। उसके बाद वे भारतीय जनसंघ से जुड़े। वहां संगठन सचिव से लेकर तत्पश्चात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के दायित्वों का उन्होंने निर्वहन किया। 1977 में ठाकरे जी अविभाजित मध्यप्रदेश के खंडवा लोकसभा से सांसद भी चुने गए थे। राजनीति के कबीर ठाकरे जी का निधन 28 दिसंबर 2003 को हो गया। ठाकरे जी की जन्मशती पर भाजपा उन्हें समर्पित 'कार्य विस्तार योजना' की शुरुआत कर रही है। इस अवसर पर कुछ प्रेरकप्रसंग के माध्यम से राजनीति के इस कबीर की जीवन गाथा बता रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय...

सादगीपूर्ण जीवन ही सन्देश

अविभाजित मध्यप्रदेश में भाजपा की प्रदेश कार्यसमिति थी बैतूल या होशंगाबाद में। सभी उपस्थित भाजपाजन अपने संगठन के सबसे बड़े शिल्पी, अभिभावक की प्रतीक्षा कर रहे थे। भीड़ भरे बैठक स्थल पर सबकी निगाहें सड़क की तरफ लगी थी। तभी पास के बस स्टैंड पर एक नियमित यात्री बस रुकी और अपना झोला लिए उतर पड़े ठाकरे जी। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य, पूर्व भाजपाध्यक्ष, ख़ासकर मध्य भारत में पार्टी के पितृ पुरुष की भूमिका में संगठन के बीज को वट वृक्ष का रूप देने वाले प्रातः स्मरणीय स्व. श्री कुशाभाऊ ठाकरे!

भाजपाजन कभी भी अतिरिक्त सुविधाभोगी होकर साध्य से भटकें नहीं, यही आशय था उस पुरोधा का। यही आशय हमेशा रहा भी ठाकरे जी का। सम्पूर्ण देश खासकर छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश में आज भाजपा के विचारों का जो प्रासाद खड़ा है, निस्संदेह उसके शिल्पकार, विश्वकर्मा अगर ठाकरे जी को कहा जाय तो रत्ती भर भी अतिश्योक्ति नहीं होगी।

प्रदेश निर्माण की आकल्पना

जहां तक छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, तो इसके निर्माण में नैपथ्य में रह कर जितनी बड़ी भूमिका का निर्वहन ठाकरे जी ने किया, वह तो हम कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रातः स्मरणीय रहेगा। मध्य प्रदेश के संगठन प्रभारी और फिर अध्यक्ष, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक ठाकरे जी के पास जैसी भी जिम्मेदारी रही हो लेकिन, छत्तीसगढ़ अंचल हमेशा उनके लिए विशेष रहा। प्रदेश के कस्बों-गावों तक का प्रवास करने वाले ठाकरे जी इस अंचल की तासीर, इसकी आवश्यकताओं और समस्याओं से भली-भांति परिचित थे। अंचल की समस्याओं के समाधान हेतु भी उनकी अपनी एक व्यापक समझ थी। ज़ाहिर है, इस आदिवासी बहुल क्षेत्र को एक अलग प्रदेश बनाना ही यहां की विसंगतियों का सबसे बड़ा समाधान होगा, ऐसा प्राणपन से मानना था ठाकरे जी का।

हम जैसे उनके अभिभावकत्व में काम शुरू किये हुए लोग जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री के रूप में अटल जी और तब के उप प्रधानमंत्री आडवानी जी नए राज्यों के निर्माण का विचार कर रहे थे तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ठाकरे जी ने ही क्षेत्र के वैशिष्ट्य की विस्तार से जानकारी देकर छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी उल्लेखनीय और प्रभावी भूमिका का निर्वहन किया था। ठाकरे जी के भाजपाध्यक्ष रहते हुए केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा छग, झारखंड और उत्तराखंड जैसे विशिष्ट प्रदेश के निर्माण का निर्णय होना उनकी एक बड़ी उपलब्धि के बतौर इतिहास दर्ज करेगा।

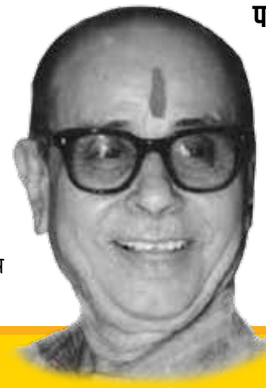

जन्मशती को समर्पित भाजपा का 'संगठन कार्य विस्तार अभियान'

परिजन जैसे वनवासी जन

छत्तीसगढ़ प्रदेश के खासकर वनवासी अंचल से ठाकरे जी के जुड़ाव के अनेक संस्मरण मानस पटल पर अंकित हो रहे हैं। ठाकरे जी के मन में आदिवासी समस्याओं के बारे में हमेशा अतिरिक्त चिंता होती थी। एक पीड़ा हमेशा उनके भीतर हम सबने देखा था उनके प्रति। उनके दुखों से हमेशा वे एकाकार से हो जाते थे। उनकी पीड़ाओं को न केवल

ठाकरे जी आजीवन अपना निजी कष्ट समझते रहे अपितु हर संभव कोशिश की उसे दूर करने की भी। वे हमेशा से यह मानते थे कि 'वनवासी कल्याण आश्रम' अत्यल्प संसाधनों में भी अपने वनवासी बंधु-भगिनियों के जीवन उत्थान हेतु तत्पर रहा है। बड़े ही रोचक और मौलिक तरीके से आश्रम को वे आर्थिक सहयोग प्रदान करते थे। मध्य प्रदेश में भाजपा के स्तंभ रहे अपने मित्र स्व. लखीराम अग्रवाल के अग्रज और विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ता स्व. रामचंद्र अग्रवाल के साथ ठाकरे जी का वन्य प्रांत में सतत प्रवास होता रहता था।

1997 में जब कार्यकर्ताओं ने ठाकरे जी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय किया तब बड़ी ही मुश्किल से इसके लिए राजी हुए वे और वह भी एक इसी शर्त पर कि इसके माध्यम से एक बड़ी राशि एकत्र की जाय और उसे भी वनवासी कल्याण आश्रम को समर्पित किया जाय। ऐसा ही हुआ भी। अद्भुत और गरिमामय कार्यक्रम संपन्न हुआ जिसे आदिवासियों के कल्याण के निमित्त समर्पित किया गया। संदर्भवश इस तथ्य का वर्णन करना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि उनके नेतृत्व वाली भाजपा के अटल जी की ही सरकार ने देश में पहली बार आदिवासियों के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन किया था, निस्संदेह उस निर्णय में ठाकरे जी की यही प्रेरणा रही होगी।

लोकसंग्रह और अपरिग्रही

कितना विराट व्यक्तित्व था, कैसे अजातशत्रु थे आदरणीय कुशाभाऊ, यह उस अमृत महोत्सव में एक बार और साबित हुआ जब सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी तब के मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह उस कार्यक्रम में उपस्थित होकर राजनीति में शुचिता के इस पुरोधा, सादगी के अग्रदूत के आगे नतमस्तक हुए थे। लोकसंग्रह और एक-एक कार्यकर्ता को गढ़ना, एक जौहरी की तरह कार्यकर्ता रुपी रत्नों की पहचान करना और फिर उसे तराशना, यह ऐसा मौलिक स्वभाव था ठाकरे जी का जिसके कारण हमेशा के लिए वे लोगों के हृदय में रहेंगे।

आत्मनिर्भर भाजपा

पार्टी आर्थिक रूप से मज़बूत हो, आवश्यकता लायक संसाधन मौजूद रहे, इसके लिए हमेशा चिंता रहती थी ठाकरे जी की लेकिन, ऐसा पूरी तरह ईमानदारी के साथ हो, पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं हो, इसकी अतिरिक्त सावधानी बरतना उनके स्वभाव में था। लोगों से भाजपा 'आजीवन सहयोग निधि' के रूप में एक राशि ले और उससे पार्टी चले, यह ठाकरे जी का ही विचार था। पहले तब के मध्य प्रदेश में इसे लागू किया गया और अब हम सब जानते ही हैं कि अब समूचे देश में इसी निधि को दल के कामकाज के लिए उपयोग में लाया जाता है।

ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया

हाथ में लिए गए कार्य को संपन्न कर लिया था महामना ने। अब उनके द्वारा गढ़ी नयी पीढ़ी को आगे का मार्ग प्रशस्त करना था। सत्ता को सुख या सुविधा का माध्यम जिसने न समझा हो कभी, उसके लिए इससे ज्यादा महत्त्व भी नहीं था इस विजय का कि राष्ट्र की सर्वोच्चता का युगों प्राचीन विचार नए सिरे से आगे बढ़ रहा था। पूरा भरोसा था उन्हें अपनी निर्मित पीढ़ियों पर। बस चंद दिन ही गुजरे, संकल्प के इस सिद्धि के एक माह भी नहीं बीते हुए थे कि ठाकरे जी एक बार और निकल पड़े थे, यात्रा इस बार अनंत की थी। 28 दिसंबर 2003 संगठन का यह संत मानो यही उद्घोष करते हुए – दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यूं की त्यूं धर दीनी चदरिया। राजनीति रूपी कोयले की खान से चमकते हीरे की तरह बिल्कुल श्वेत, धवल, निर्विवाद, निष्कलंक, स्थितिप्रज्ञ...! ●●●

संकल्प की सिद्धि

सन 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और उसी वर्ष वे भाजपा के अध्यक्ष पद के दायित्व से मुक्त हुए। तीन वर्ष के कठिन संघर्ष एवं तपस्या के बाद छत्तीसगढ़ में अंततः वह दिन आ ही गया था जिसकी प्रतीक्षा पिछले दशक भर से इस निष्काम कर्मयोगी को भी थी। सात दिसंबर 2003। नवनिर्मित छत्तीसगढ़ में जहां डा. रमन सिंह जी को प्रदेश के पहले निर्वाचित मुखिया के रूप में शपथ लेना था, वहीं उसी दिन मध्यप्रदेश में साध्वी सुश्री उमा भारती जी शपथ ग्रहण करने वाली थी। रायपुर का पुलिस परेड मैदान ! हज़ारों लोग एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो चुके थे। अस्वस्थता के बावजूद शपथ ग्रहण में ठाकरे जी उपस्थित हुए। इसी ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए मानो भौतिक जगत में रुके भी हुए थे ठाकरे जी।

भाजपा का हर बूथ होगा मजबूत

भाजपा के प्रदेशव्यापी कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना का शुभारंभ हुआ। इस अभियान में प्रदेश के प्रमुख पदाधिकारियों ने अपने-अपने मंडलों व बूथ केन्द्रों में जाकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की।

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय जशपुर जिले के कुनकुरी के पंडरीपानी फरसाबहार मंडल के गजियाडीह शक्तिकेन्द्र व जामटोली बूथ में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बूथ की मजबूती को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मिशन 2023 के लिए हमारे सभी कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। प्रदेश के सभी जिलों के मंडल, शक्तिकेन्द्र व बूथ पर जाकर पार्टी द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। केन्द्र सरकार के जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने एवं प्रदेश की कांग्रेस सरकार की असफलता को बताने के लिए बूथ स्तर से लेकर शक्तिकेन्द्र व मंडलों में पार्टी के कार्य विस्तार योजना के तहत कार्यकर्ताओं के साथ जनता से सीधा संपर्क किया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक बिल्हा के सिरगिट्टी मंडल के बूथ क्रमांक 228 तिफरा व शक्ति केंद्र कालिकानगर में जाकर कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना के माध्यम से बूथ में जाकर उन बूथों के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया तथा पार्टी द्वारा सौंपे गए कार्यों की विस्तार से जनकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्य विस्तार योजना के तहत प्रत्येक कार्यकर्ता को शक्तिकेन्द्र के सभी बूथों में जाकर कार्यकर्ताओं से संवाद करना है।

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल रायपुर के बूथ में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बूथों को मजबूती का सकारात्मक प्रतिसाद 2023 के विधानसभा में हमें देखने को मिलेगा। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने बूथों की मजबूती को लेकर लगातार कार्य कर रहे है। हमें अपने हर बूथ को मजबूत करना है तथा आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की भ्रष्ट और कमीशनखोर सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकना है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी ने स्व. कुशाभाऊ ठाकरे जी के जन्मशताब्दी वर्ष पर सभी शक्ति केंद्रों में विस्तारक के प्रवास कार्यक्रम के तहत ग्राम टेडेसरा, मंडल घुमका विधानसभा राजनांदगांव बूथ के प्रभारी एवं सह प्रभारी कार्यकर्ताओं से मुलाकात एवं चर्चा की।

राज्यसभा सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय दुर्ग जिले के पटरीपार मंडल में कार्य विस्तार योजना के तहत पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है तथा उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि बूथ से ही जीत की शुरुआत होती है अगर आप बूथ जीत गए तो चुनाव में आपकी जीत निश्चित है।

प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री अजय चंद्राकर कुरूद शहर के बूथ में संपर्क कर प्रदेश सरकार की विफलताओं को बताया और केन्द्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता व पूर्व मंत्री श्री केदार कश्यप भानपुरी मंडल के करनदोला में कार्य विस्तार अभियान में शामिल हुए। उन्होंने प्रदेश सरकार को हर मोर्चे पर असफल बताया। भाजपा के प्रमुख पदाधिकारी, सांसद, विधायक, अपने संसदीय व विधानसभा क्षेत्र में शामिल हुए।

डिलिस्टिंग को लेकर क्यों इतना मुखर है जनजाति समाज

पंकज सिंह

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जनजातीय/वनवासी बहुल क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा राष्ट्रीय स्तर पर कम ही देखने को मिलती है। वास्तविकता में ये कहने में कोई अतिश्योक्ति नहीं होनी चाहिए कि वर्ष 2014 से पहले कमोबेश संबंधित भारतीय सरकारों ने मोटे तौर पर ना केवल विकास कार्यों के संदर्भ में इन क्षेत्रों की उपेक्षा की है अपितु कभी भी वनवासी या जनजातीय समुदाय के उत्थान के विषय में भी गंभीरता से विचार नहीं किया और यह केवल 2014 के बाद ही है कि केंद्र सरकार ना केवल समुदाय के गुमनाम नायकों के योगदान को रेखांकित कर उन्हें राष्ट्रीय पटल पर पहचान दिला रही, बल्कि समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में भी गंभीर प्रयास कर रही है, परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में परिवर्तन अब दिखाई भी देने लगा है।

हालांकि जनजातीय बहुल क्षेत्रों में सरकार के इन नेक प्रयासों के बावजूद जनजातीय समुदाय वर्तमान में मिशनरियों और कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों द्वारा सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कराए जा रहे अवैध धर्मांतरण से अपने अस्तित्व पर एक गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। स्थिति ऐसी है कि समुदाय के लोगों का मानना है कि यदि अवैध धर्मांतरण की मौजूदा प्रवृत्ति जारी रही तो मिशनरियों एवं जिहादी गुटों का यह षड्यंत्र उनकी सांस्कृतिक पहचान को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर देगा। यही कारण है कि समुदाय के नेता अब धर्मांतरण कर चुके लोगों को डिलिस्टिंग के माध्यम से जनजातीय वर्ग से बाहर किए जाने की मांग का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं।

समुदाय के अग्रणी लोगों का मत स्पष्ट है कि ईसाई मिशनरी और जिहादी तत्व विभिन्न अवैध तरीकों से लोगों को दूसरे धर्म मे परिवर्तित कर रहे हैं इसके लिए उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जैसे कि हिंदू धर्म के बारे में भ्रम फैलाना, इलाज के नाम पर सहायता या आदिवासी लड़कियों (लव जिहाद) से शादी करना, अब ऐसे में समाज के रूप में समुदाय को अपनी लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी।

समुदाय के अग्रणी लोगों का मत स्पष्ट है कि ईसाई मिशनरी और जिहादी तत्व विभिन्न अवैध तरीकों से लोगों को दूसरे धर्म मे परिवर्तित कर रहे हैं इसके लिए उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं।

समाज के प्रबुद्ध लोगों का मानना है कि पिछले एक या दो दशक में जनजातीय समुदाय के भीतर धर्मान्तरित लोगों की संख्या अप्रत्याशित रूप से बढ़ी है। उनके मत में पिछले 10 वर्षों के भीतर, समुदाय के लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में ईसाई मिशनरियों के दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है और इस कुकृत्य को बढ़ावा देने के लिए पहले की अपेक्षा अब वे धन बल का जमकर दुरूपयोग कर रहे हैं, उनके पास इसके लिए धन की कोई कमी नहीं है और अब वे इसे जनजातियों को परिवर्तित करने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण के रूप में दुरुपयोग कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त चर्च, पादरी और उनके सभी तंत्र अब ईसा मसीह के साथ भारतीय देवी-देवताओं के साथ कुछ समानता का हवाला देते हुए बड़ी ही धूर्तता से समुदाय के लोगों का धर्मांतरण कर रहे हैं

दिलचस्प यह भी है कि बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वोत्तर राज्य, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर तमिलनाडु का सबसे दूरस्थ क्षेत्र, मिशनरियों की कार्य प्रणाली बिल्कुल एक जैसी है। मिशनरी पहले ईसाई धर्म एवं इन क्षेत्रों के जनजातीय व्यक्ति की धार्मिक पहचान के बीच समानता का हवाला देते हैं और फिर धूर्तता से भ्रम अथवा पैसे का लालच देकर उनका धर्मांतरण करा देते हैं।

समुदाय के लिए बड़ी चिंता यह भी है कि धर्मान्तरित व्यक्ति भले ही सार्वजनिक रूप से ईसाई धर्म की मान्यताओं का पालन कर रहा हो, कागज पर वो हिंदू ही रहता है ताकि धर्मांतरित व्यक्ति को सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ उसे मिलता रहे। समुदाय के लोगों का मानना है कि इससे समाज के भीतर गलत संदेश जा रहा है जिसे तात्कालिक रूप से रोके जाने की आवश्यकता है

हालांकि जनजातीय समुदाय को लक्षित कर चलाए जा रहे धर्मांतरण के कुकृत्य के पीछे ना केवल ईसाई मिशनरियों की सहभागिता है अपितु अब जब की पूरा देश लव जिहाद के रूप में कट्टरपंथी तत्वों द्वारा रचे गए सुनियोजित षड्यंत्र का सामना कर रहा है, जनजातीय समुदाय भी इसका अपवाद नहीं है।

इस संदर्भ में हाल ही में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें जनजातीय समुदाय की युवतियों को झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश एवं पश्चिम बंगाल में लव जिहाद का शिकार बनाया गया है।

सुदूर पिछड़े क्षेत्रो में निवासरत इन युवतियों

को कई मौकों पर ना केवल जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार बनाया गया है बल्कि कई ऐसे भी प्रकरण सामने आए हैं जहां पहचान छुपाकर युवती के साथ संबंध स्थापित कर उसे निकाह एवं धर्मांतरण के लिए बाध्य किया गया हो।

ऐसे प्रकरणों में कई स्थानों पर तो युवती से संबंधित पैतृक भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं अतिक्रमण से संबंधित खबरे भी प्रकाश में आई हैं, हालांकि तुष्टीकरण की नीति के कारण संबंधित सरकारों द्वारा ऐसे अपराधियों पर कठोर कार्यवाई भी नहीं की जाती।

अब जनजातीय बहुल क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियों एवं कट्टरपंथी द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे धर्मांतरण के इस कुकृत्य को लेकर आम तौर पर शांतिप्रिय माने जाने वाले समुदाय के भीतर भी रोष पनपने लगा है, समाज के लोगों का मत है कि यदि वे इस सुनियोजित षड्यंत्र के विरुद्ध खड़े ना हुए तो यह केवल समय की बात है जब उनके पारंपरिक पहचान संकट में आ जाएगी, यही कारण है कि वे अब इसका सर्वसम्मति से मुखर विरोध कर रहे हैं।

इस संदर्भ में हालिया एक दो वर्षों में हुए प्रदर्शनों के दौरान जनजातीय समाज के प्रबुद्ध जनों ने जनजाति बहुल क्षेत्रों में डिलिस्टिंग कराए जाने की मांग करते हुए इन क्षेत्रों में सरकार द्वारा तत्काल प्रभाव से जनजाति वर्ग की सूची को पुनः निर्धारित किए जाने की बात कही है। इन प्रदर्शनों में मांग की गई है कि सरकार यह जांच करे कि संबंधित व्यक्ति जो कागजों पर समुदाय का हिस्सा होने का दावा कर रहा है, वह अभी भी समुदाय के रीति-रिवाजों और परंपरा का पालन कर रहा है या उसने उसका परित्याग कर कोई और पंथ स्वीकार कर लिया है। समुदाय की मांग है कि सनातन धार्मिक परंपराओं के इतर यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पंथ की मान्यताओं का अनुपालन करता पाया जाता है तो उसे आरक्षण जैसे लाभ से तत्काल प्रभाव से वंचित किया जाना चाहिए।

हालांकि जहां एक ओर जनजातीय समुदाय जनजातीय वर्ग को असूचीबद्ध करने की मांग का समर्थन कर रहा हैं, वहीं दूसरी ओर कम्युनिस्ट संचालित शक्तियां इस प्रस्तावित मांग का पुरजोर विरोध कर रही हैं। इस संदर्भ में वामपंथी तथाकथित बुद्धिजीवियों का कुतर्क यह है कि जनजाति समुदाय का मत है कि जो जनजाति बौद्ध, सिख या जैन धर्म में परिवर्तित हो गए, उन्हें आरक्षण या अन्य लाभों से वंचित नहीं किया जाए। अब समुदाय की इस मांग को वामपंथी समूह पक्षपातपूर्ण बताने पर आमादा है, हालांकि अपने कुतर्कों का प्रचार करते हुए वामपंथी समूह यह भूल रहा है कि इन धर्मों में धर्मांतरण को बढ़ावा देने के लिए न तो ईसाई धर्म जैसा कोई मिशनरी तंत्र है और न ही इस्लाम जैसी धार्मिक माध्यमों से सत्ता हथियाने की उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा है।

बहरहाल इन सब के बीच इसमें कोई संशय नहीं कि जनजातीय समुदाय की डिलिस्टिंग समय की मांग है और यह सरकार को तय करना है कि इसे लागू करने के लिए कानूनी रूप से एक तंत्र का गठन करने के लिए उसे कितना समय चाहिए। हालांकि जब तक सरकार इस दिशा में ठोस पहल नहीं करती तब तक के लिए तो अवैध धर्मांतरण जैसे कृत्य के विरुद्ध जनजाति समाज को ही कमर कसनी होगी। ●●●

महाझूठी है कांग्रेस सरकार

आत्मनिर्भर रहे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने शोषित और केंद्र आश्रित प्रदेश बनाया

हम सबने देखा, सुना और भुगता भी है कि कोरोना ने विश्व की कई अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त किया भारत की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई। उसके बावजूद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दी गई मदद उनके लिए संजीवनी से कम नही है। वर्ष 19/20 में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को लगभग 34 हजार करोड़ रूपये दिए जो राज्य की कुल आय का 53 प्रतिशत है, यानी केंद्र से मिली राशि राज्य की खुद की आय से ज्यादा रही।वर्ष 20/21 में भी हालत कुछ ऐसे ही थे केंद्र सरकार ने राज्य को लगभग 38 हजार करोड़ रु दिए। वर्ष 21/22 में लगभग 44 हजार करोड़ और आने वाले वर्ष के लिए केंद्र से 44,573 करोड़ मिलना प्रस्तावित है। हर वर्ष केंद्र से मिली या मिलने वाली राशि कांग्रेस शासन में राज्य की कुल आय से ज्यादा है।

इस वर्ष के केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार ने राज्यों के विकास के लिए 2 लाख 92 हजार करोड़ की राशि अलग से पूजीगत व्यय के लिए आवंटित की है, जिसमें 8 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है। कांग्रेस शासन में छत्तीसगढ़ को करों की हिस्सेदारी के रूप में केवल 32 प्रतिशत राशि मिलती थी लेकिन मोदी सरकार में अब हमारे राज्य को केन्द्रीय करों का 42 प्रतिशत हिस्सा मिल रहा है। खुस लम्बे समय तक मुख्यमंत्री रहे माननीय मोदी जी ने सीधे दस प्रतिशत राज्यों का हिस्सा बढाया। शर्मनाक है कि इन सारे तथ्यों के बावजूद कांग्रेस सरकार निर्लज्जता के साथ झूठ पर झूठ परोस रही है। केंद्र से मिलने वाली ग्रांट में प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और पहले से छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र से 178 प्रतिशत राशि ज्यादा मिल रही है।केंद्र द्वारा इतना सबकुछ देने के बाद भी राज्य का अनर्गल आरोप लगाना संघीय व्यवस्था उस अनैतिकता का चरम है, जिसके लिए कांग्रेस को हम सब जानते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा मा. प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में 3 वर्षों के बजट अनुमानों के आधार पर इस आंकड़े के गणना की गई है, इससे अधिक हास्यास्पद मूर्खता और कुछ नहीं हो सकती है। राज्य सरकारों की देनदारी या लेनदारी बजट अनुमानों के आधारों पर तय नही होती। राज्य सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी के रूप में मांगी जाने वाली 13 हजार करोड़ की राशि पूरी तरह गलत है।

इस वर्ष के केंद्रीय बजट में केंद्र ने राज्यों के विकास के लिए 2 लाख 92 हजार करोड़ की राशि अलग से पूजीगत व्यय के लिए आवंटित की है, जिसमें 8 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त लाभ छत्तीसगढ़ को मिलने जा रहा है।

प्रदेश सरकार से भाजपा कुछ सवाल करना चाहती है

1. कांग्रेस के सभी नेता केंद्र के पास छत्तीसगढ़ राज्य की लंबित राशि का आंकड़ा अलग-अलग क्यों बताते हैं? कोई कहता है केंद्र से 20 हजार करोड़ लेना है, कोई 24 हजार करोड़, कोई 30, कोई 35 हजार करोड़ !

2. अगर कथित तौर पर इतनी बड़ी राशि लंबित है, तो कांग्रेस के सांसदों ने इस विषय को कितनी बार लोकसभा और राज्य सभा में उठाया,और नही उठाया तो क्यों नही उठाया?

3. राज्य सरकार द्वारा मांगी जाने वाली राशि में 13 हजार करोड़ एक्साइज ड्यूटी का लंबित बताया गया है वह किस वस्तु की एक्साइज ड्यूटी है?

4. भाजपा राज्य सरकार को चुनौती देती है कि राज्य सरकार केंद्र से मांगी जानी वाली राशि को या बजट 2022-23 में केन्द्र से छत्तीसगढ़ के लिए प्रावधानपूजीगत व्यय के लिएछत्तीसगढ़ कोप्रमाणित करे नही तो केंद्र सरकार के बारे में मिथ्या आरोप लगाने के लिए जनता से माफी मांगे।

केन्द्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है, और राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है, तो मोदी सरकार करों में हिस्सेदारी में छत्तीसगढ़ राज्य को 3 गुना से अधिक राशि मिल रही है। जबकि कांग्रेस सरकार थी यही प्रतिवर्ष मात्र 6,245 करोड़ औसत थी।

पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8 हजार करोड़ रूपये ज्यादा मिलेंगे।छत्तीसगढ़की कांग्रेस सरकारबार बारभाजपा की केंद्र सरकार पर भेदभाव व पैसे न देने का आरोप लगाती है यदि आप केंद्र से पिछले 3 वर्षो में मिली राशि के आंकड़े पर नजर डालेंगे तो शायद आपके पैरों से जमीन खिसक जाए,कोई भी सोच नही सकता कांग्रेस इतना पैसा मिलने के बावजूद भी झूठ का प्रचार क्यों कर रही है? यह आंकड़े आपको आभास कराएंगे कांग्रेस की राजनीति का स्तर कितना नीचे गिर चुका है।

केन्द्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार है, और राज्य में भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार है, तो मोदी सरकार करों में हिस्सेदारी में छत्तीसगढ़ राज्य को 3 गुना से अधिक राशि मिल रही है। जबकि कांग्रेस सरकार थी यही प्रतिवर्ष मात्र 6,245 करोड़ औसत थी।

इतनी राशि मिलने के बाद भी राज्य सरकार और कांग्रेस के नेताओ को केंद्र पर आरोप लगाते लज्जा नहीं आती।आज की तारीख में राज्य द्वारा केंद्र से मांगी जाने वाली राशि का सच जाने।

राज्य सरकार का दावा है कि केंद्र से 13 हजार करोड़ एक्साइज ड्यूटी के नही मिले ! जबकि तथ्य यह है कि चौहदवे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार जिसकी अध्यक्षता श्री वी वाई रेड्डी ने की में राज्यों की केंद्रीय करों में हिस्सेदारी को 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत किया गया। इन करों में एक बड़ा हिस्सा एक्साइज ड्यूटी का भी है।इन करों की हिस्सेदारी को रोका भी नहीं जा सकता अतः राज्य सरकार का क्लेम पूरी तरह झूठा है।

केन्द्र से छत्तीसगढ़ को मिली राशि

क्र.	वर्ष	करों में हिस्सेदारी के रूप में राशि	ग्रांट के रूप में मिली राशि	केन्द्र में शासन
1.	2012-14	18,734 करोड़	13,364 करोड	कांग्रेस
2.	2019-22	63,217 करोड़	53,761 करोड़	भाजपा
3	2012-14	मात्र 6,245 करोड़ (प्रतिवर्ष औसत)	मात्र 4,445 करोड़ (प्रतिवर्ष औसत)	कांग्रेस
4	2019-22	मात्र 21,072 करोड़ (प्रतिवर्ष औसत)	मात्र 17,920 करोड़ (प्रतिवर्ष औसत)	भाजपा

राज्य सरकार के इस दावे को खारिज करते अन्य प्रमाण

1 छत्तीसगढ़ विधानसभा में 8 मार्च 2022 को पूछे गए प्रश्न के जवाब में लंबित एक्साइज ड्यूटी का आंकड़ा महज 520 करोड़ दिया गया है जबकि कांग्रेस के नेता अपने भाषणों, व मीडिया में इसे 13 हजार करोड़ कह रहे हैं।

2 मुख्यमंत्री द्वारा मा. प्रधानमंत्री को लिखे गए प्रत्र में जब 13 हजार करोड़ की मांग की गई तब यह साफ लिखा था कि 3 वर्षों के बजट में जो अनुमानित राशि मिलनी थी उससे 13 हजार करोड़ कम मिला है।

यह बात स्वयं पुष्टि करती है 13 हजार करोड़ की एक्साइज ड्यूटी की मांग गलत है क्योंकि बजट एक अनुमान होता है तथा राज्यों को करो में हिस्सेदारी बजट के आधार पर नही बल्कि वास्तव में प्राप्त किए गए कर से मिलती है।

कांग्रेस का दूसरा झूठ 14 हजार करोड़ जीएसटी क्षतिपूर्ति के लंबित है

तथ्यः विधानसभा में पूछे गए प्रश्न के जवाब में यह स्वीकार किया गया है की वर्ष 2019/20 व वर्ष 20/21 की जीएसटी की क्षतिपूर्ती की जितनी राशि मिलनी थी मिल चुकी दोनो वर्षो में मिली यह राशि क्रमशः 3081.44 करोड़, 3212.15 करोड़ है।

जीएसटी क्षतिपूर्ति मिली

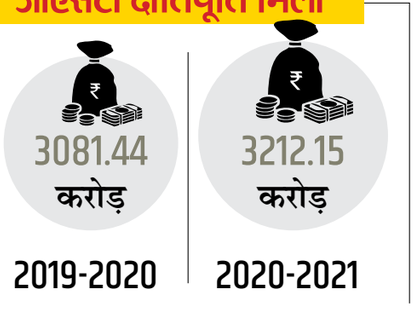

केवल 21/2022 की राशि लंबित है जो कि लगभग 3,500 करोड़ के आस पास है। वो भी इसीलिए की वर्ष खतम हुए अभी 30 दिन भी नही हुए।आप अंदाजा लगाए छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किस प्रकार महाझुठ कहती है व किस स्तर तक गिर चुकी है।

सांसद श्री सुनील सोनी की प्रेस वार्ता और सीए श्री अमित चिमनानी द्वारा किये रिसर्च से संकलित.

छत्तीसगढ़ को मिलेगा एक लाख करोड़ की सड़क

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने रायपुर में 9,240 करोड़ रुपये की 33 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं से छत्तीसगढ़ को ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से जुड़ने में सहायता मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के पिछड़े क्षेत्रों को राज्य के विकसित इलाकों से जोड़ने के लिए सुगम सड़क नेटवर्क उपलब्ध होगा और मुंगेली तथा कबीरधाम में स्थित सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थलों तक पहुंचना भी आसान हो जायेगा।

श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार छत्तीसगढ़ की समृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इन सड़क परियोजनाओं के निर्माण से ईंधन, यात्रा समय, दूरी और कुल परिवहन लागत में कमी आयेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन विकास कार्यों से अनूपपुर-अंबिकापुर के कोयला व भारी रेल यातायात जोन में सड़क यातायात सुचारू हो जायेगा और इनसे भारी तथा बड़े वाहनों के आवागमन में आसानी होगी। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन परियोजनाओं से व्यावसायिक केंद्रों, वाणिज्यिक वाहन केंद्रों, खानों और प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्रों तक पहुंचने में भी बहुत आसानी होगी। नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है पानी, पावर कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी राज्य आगे बढ़ सकता है। श्री गडकरी ने यहां पर 9240 करोड़ के 1017 किलोमीटर की 33 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि हम आने वाले पांच साल में छत्तीसगढ़ में ऐसी सड़कें बनवा देंगे जो अमेरिका जैसी होंगी। मैंने अपने दफ्तर में अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडी की कही एक बात को चिपका कर रखा है। वह कहा करते थे कि अमेरिका धनवान है, इस वजह से वहां की सड़कें अच्छी नहीं हैं, बल्कि सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका धनवान है।

गडकरी ने कहा कि सड़कों के विकास का महत्व समझाने वाली इन बातों को मैं हमेशा महत्व देता हूं। मैं हमेशा मानता हूं और चाहता हूं कि इसी रास्ते पर छत्तीसगढ़ भी आगे बढ़े। नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आग्रह करते हुए कहा कि जमीन और फॉरेस्ट क्लीयरेंस के मामलों को आप जितनी जल्दी आगे बढ़ाते जाएंगे, मैं वादा करता हूं कि साल 2024 तक छत्तीसगढ़ को एक लाख करोड़ की सड़कें बनाकर एनएचएआई की तरफ से दी जाएंगी।

नितिन गडकरी ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है पानी, पावर कम्युनिकेशन, और ट्रांसपोर्ट इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी राज्य आगे बढ़ सकता है। छत्तीसगढ़ में भी हमें ऊर्जा संचार यातायात और पानी से संबंधित व्यवस्थाओं पर ध्यान देना होगा। इससे कृषि बढ़ेगा कृषि बढ़ेगा तो किसानों की आर्थिक स्थिति होगी अच्छी होगी।

भूपेश की तानाशाही

लोकतंत्र बचाने छत्तीसगढ़ में एक लाख भाजपायी सड़क पर उतरे

डरी, घबराई सरकार प्रदेश में आपातकाल लागू किए हुए है : श्री विष्णुदेव साय

अंग्रेजों की राह चल रही कांग्रेस, अंग्रेज चले गए लेकिन दमन की उनकी विचारधारा आज भी कांग्रेस के रूप में जिंदा: डॉ. रमन सिंह

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने भूपेश सरकार के काला कानून के विरोध में प्रदेश भर में प्रदर्शन कर अपनी गिरफ्तारी दी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के सत्तर हजार से अधिक कार्यकर्ताओं ने पूरे प्रदेश भर में अपनी गिरफ्तारी दी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भाजपा की प्रांतीय बैठक में भूपेश सरकार को 15 दिन में काला कानून वापस लेने का समय दिया था लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार के अड़ियल रवैए के बाद पूरे प्रदेश में 16 मई को जेल भरने के लिए सभी जिलों में भाजपा के संगठन व पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी गिरफ्तारी दी।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपने गृह जिले जशपुर में आंदोलन का नेतृत्व किया और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपने विरोध को सहन नहीं कर पा रही है। जबकि जनता व कर्मचारियों से किए गए वादे को पूरा न कर पाने के कारण हर जगह राज्य सरकार का विरोध आंदोलन की शक्ल ले रहा है। डरी, घबराई सरकार प्रदेश में पुनः आपातकाल लागू किए हुए है। जिसका पूरी ताकत से भाजपा विरोध करती है।

भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने बड़े-बड़े वादे तो किए थे लेकिन जब उन वादों को पूरा करने का समय आया तो वह उसे पूरा नही कर रही है। जिसके कारण प्रदेशभर के विभिन्न कर्मचारी संगठन, किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मनरेगा कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, विद्युतकर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार का विरोध कर रहे थे जिसको दबाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक काला कानून (भूपेश एक्ट) लाकर लोकतंत्र की आवाज को दबाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार सन 1975 की तर्ज पर प्रदेश में अघोषित आपातकाल लागू कर दिया है जिसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। प्रदेश सरकार का यह तानाशाही रवैया कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इस दौरान जेल भरो आंदोलन में रायपुर में प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय, पुर्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुन्दरानी, अभिनेष कश्यप, संजय श्रीवास्तव, मोतीलाल साहू, नरेश गुप्ता, दीपक म्हस्के, नलिनीश ठोकने, मीनल चौबे, केदार गुप्ता देवजी भाई पटेल, नंदे साहू, ओंकार बैस, सूर्यकांत राठौर, राजीव अग्रवाल, मृत्युंजय दुबे, अमित मैशरी, अमित चिमनानी गोविंदा गुप्ता, अर्पित सूर्यवंशी, सीमा साहू, किरण बघेल, राम प्रजापति, राहुल राव, संयोगिता जुदेव, राजेश पाण्डेय बलौदाबाजार-भाटापारा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, विधायक शिवरतन शर्मा, सनम जांगड़े, दुर्ग में सांसद सुश्री सरोज पाण्डेय, विजय बघेल, बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, अमर अग्रवाल, भूपेन्द्र सवन्नी, कांकेर में सांसद मोहन मंडावी, पूर्व सांसद विक्रम उसेंडी, शालिनी राजपूत, सतीष लाठिया, जगदलपुर में प्रदेश महामंत्री किरण देव, दिनेश कश्यप, सुभाऊ कश्यप, संतोष बाफना, नारायणपुर में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, कोंडागांव में लता उसेंडी, दीपेश अरोरा, मनोज जैन, प्रदीर बदेशा, बीजापुर में डी. वेंकट, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, सुखलाल पूजारी, रायगढ़ में सांसद गोमती साय, ओपी चौधरी, सरगुजा में कमलभान सिंह, अनुराग सिंहदेव, मेजर अनिल सिंह, जांजगीर-चांपा में सांसद गुहाराम अजगले, नारायण चंदेल, कोरबा में ननकी राम कंवर, राजीव सिंह, लखनलाल देवांगन, कवर्धा में सांसद संतोष पाण्डेय, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, विजय शर्मा, धमतरी में पूर्व मंत्री व विधायक अजय चंद्राकर, रंजना साहू, गरियाबंद में पूर्व सांसद चंदूलाल साहू, डमरूधर पूजारी, संदीप शर्मा, संतोष उपाध्याय, गोवर्धन मांझी, राजेश साहू, श्वेता शर्मा, रामकुमार साहू, महासमुंद में रूप कुमारी चौधरी, पूनम चंद्राकर, विमल चोपड़ा, इंद्रजीत सिंह गोल्डी, सरला कोसरिया, सहित बहुत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।।

राजनांदगांव में मुख्य वक्ता की आसंदी से पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव की संस्कारधानी में विभिन्न त्योहार आयोजित किए जाते हैं, जिसके लिए शोभायात्रा के रूप में जुलूस निकाले जाते हैं, जिसमें गणेश चतुर्थी हनुमान जयंती, महावीर जयंती, प्रकाश पर्व, ईद, अंबेडकर जयंती, बुद्ध जयंती एवं विभिन्न प्रकार के आयोजनों में प्रशासन की 19 बिंदुओं की सहमति पत्र भरना एवं उस प्रारूप के अंतर्गत आयोजकों की जवाबदारी होना असंभव प्रतीत होता है, उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है मानो भूपेश सरकार अपने कार्यकाल से परेशान जनता के हाव-भाव को समझ चुकी है, इसलिए आज लगभग 4 वर्षों में जो घोषणा पत्र में भूपेश सरकार ने वायदे किए थे, उसमें सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इसलिए सभी क्षेत्र सभी वर्ग के लोगों ने सरकार के खिलाफ आने वाले समय में आंदोलन प्रदर्शन की रूपरेखा तय की है, जिसमें पटवारी, आंगनबाडी महिलाएं, स्व सहायता समूह, शिक्षकगण एवं कर्मचारीगण बेरोजगार युवा, शराब से पीड़ित महिलाएं, इत्यादि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका है, इसलिए ऐसे आंदोलनों को कुचलने का कुत्सित प्रयास प्रदेश में बैठी हुई भूपेश सरकार कर रही है। लोकतंत्र के इस स्वरूप में विपक्ष की आवाज को दबाने का जो प्रयास प्रदेश में बैठी हुई सरकार कर रही है। उसे भाजपा इस आंदोलन के माध्यम से चेतावनी देना चाहती है कि अगर इस गिरफ्तारी एवं आंदोलन के पश्चात भूपेश सरकार ने यह कानून वापस नहीं लिया तो भाजपा चैन से नहीं बैठेगी और इससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने बिलासपुर में इस काले कानून का पुरजोर विरोध करते हुए तत्काल इसे वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिये कांग्रेस सरकार लोगों की स्वतंत्रता का हनन करना चाहती है। कांग्रेस सरकार ने चुनाव पूर्व जितनी भी घोषणाएं की उस पर आज तक अमल नहीं किया। अनियमित संविदा कर्मचारियों को सत्ता में आते ही नियमित करने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढाने बेरोजगारी भत्ता देने किसानों मजदूरों महिलाओं के साथ धोखाधड़ी किया। झूठे आश्वासन देकर जनता को भ्रमित कर उन्हें ठगा। अब यही जनता आगामी चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखायेगी। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने भूपेश सरकार को डरपोक बताते हुए कहा कि 19 बिंदु के काला कानून जो सरकार ने लागू किए हैं वह गैरकानूनी है। यह कानून सरकार ने हड़बड़ा कर एवं डरकर लागू किया है क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान झूठ का सहारा लेकर बड़े-बड़े वादे कर प्रदेश की जनता को ठग तो लिया लेकिन अब जो वायदे कांग्रेस ने किए थे अब उसे लागू करने में तथा पूरा करने में पसीने छूट रहे हैं। कर्मचारियों से लेकर किसानों से लेकर प्रदेश के आम जनमानस में भूपेश सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश दिखने लगा है। अब कांग्रेस को डर सताने लगा है इसलिए इस काले कानून के आड़ में आंदोलन कर रहे मितानिन हो शासकीय कर्मचारी हो चाहे अन्य संगठन या संस्थाएं इनकी आवाज को दबाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र रच कर गुंडागर्दी पर यह सरकार उतारू हो गई है।

भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय जेल परिसर में भूपेश सरकार की सद्बुद्धि हेतु किया हनुमान चालीसा का पाठ

प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय जी ने भी ने दी गिरफ्तारी

भाजपा प्रदेश महामंत्री भूपेन्द्र सवन्नी ने कहा कि कांग्रेस ने जो वादा खिलाफी किया है उसका आम जनमानस पर असर दिखने लगा है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर उठते देख कर सरकार ने 19 शर्तो के साथ 15 बिन्दु का आवेदन पत्र का प्रारूप शपथ पत्र के साथ आयोजन के पूर्व जमा करने का आदेश जारी किया है जिसका भाजपा कार्यकर्ता विरोध करते है।●●●

नरेन्द्र मोदी

प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता देश के सपनों के प्रतिनिधि हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस पर 6 अप्रैल, 2022 को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया और उनसे देश के नवनिर्माण में और जन-जन की सेवा में कटिबद्ध होकर महती भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर श्री मोदी के उद्बोधन की आलेख प्रस्तुति ...

भाजपा के 42वें स्थापना दिवस पर जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, संगठन और पार्टी के निर्माण में खुद को खपाने वाले सभी नाम-अनाम महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक भाजपा 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। इस बार का स्थापना दिवस तीन और वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है— तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही हैं। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले चार राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी हैं। तीन दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है।

वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से, भाजपा और भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों के प्रतिनिधि हैं, देश के संकल्पों के प्रतिनिधि हैं। इस अमृतकाल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है। लोकल को ग्लोबल बनाने की है। सामाजिक न्याय की है। समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर विचार के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई। ये अमृतकाल हमारे कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है और खुद को खपा देना है। हमारी सरकार राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रही है। आज देश के पास नीतियां भी हैं, नीयत भी है।

एक समय था जब लोगों ने मान लिया था कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा। चारों ओर निराशा ही निराशा का वातावरण व्याप्त था, लेकिन आज देश का एक-एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है। तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया के सामने एक ऐसा भारत है, जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों के लिए अडिग रहता है। जब पूरी दुनिया दो विरोधी ध्रुवों में बंटी हो, तब भारत को एक देश के रूप में देखा जा रहा है, जो दृढ़ता के साथ मानवता की बात कर सकता है। आज देश के पास निर्णय शक्ति और निश्चय शक्ति भी है। आज हम लक्ष्य तय कर रहे हैं और उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही देश ने 400 बिलियन डॉलर यानी 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उत्पादों पर एक्सपोर्ट का टारगेट पूरा किया है। कोरोना काल में ये टारगेट पूरा करना भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। भारत कोरोना की लड़ाई को संसाधनों से लड़ रहा है, लगातार जीतने का प्रयास कर रहा है। आज भारत 180 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज देने वाला देश है। इतने मुश्किल समय में भारत 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन दे रहा है।

एक समय था जब लोगों ने मान लिया था कि सरकार किसी की भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा। चारों ओर निराशा ही निराशा का वातावरण व्याप्त था, लेकिन आज देश का एक-एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है।

हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की है। कुछ लोगों को ही वायदे करो, ज्यादातर लोगों को तरसा कर रखो। भेदभाव, भ्रष्टाचार... ये सब वोट बैंक की राजनीति का साइड इफेक्ट था। भाजपा ने इस वोट बैंक की राजनीति को टक्कर दी और इसके नुकसान देश को समझाने में सफल रही है। भाजपा की नेकनीयत से किए जाने वाले कामों की वजह से जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। आज दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, किसानों, नौजवानों के साथ ही जिस तरह महिलाएं भाजपा के पक्ष में मजबूती से खड़ी हुई हैं, वो अपने आप में नए युग की ताकत का प्रतिबिम्ब हैं। भाजपा का विजय तिलक करने में सबसे आगे माताएं-बहनें आती हैं। ये चुनावी घटना नहीं, सामाजिक और राष्ट्रीय जागरण है जिसका इतिहास में विश्लेषण किया जाएगा। महिलाओं में सुशासन और कड़े कानूनों से सुरक्षा का भाव हमने पैदा किया। स्वास्थ्य से लेकर रसोई की चिंता की है। मातृशक्ति में आत्मविश्वास पैदा हुआ है जो भारत को नई दिशा दे रही है। विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना हमारा दायित्व है।

आज़ादी के इस अमृत काल में हमने सैचुरेशन यानी जनकल्याण की हर योजना को शत-प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया है, वो बहुत विराट है। सैचुरेशन तक पहुंचने के इस अभियान का मतलब है— भेदभाव की सारी गुंजाइश को खत्म करना, तुष्टिकरण की आशंकाओं को समाप्त करना, स्वार्थ के आधार पर लाभ पहुंचाने की प्रवृत्ति को खत्म करना और समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे, ये सुनिश्चित करना।

हमारे लिए राजनीति और राष्ट्रनीति साथ-साथ चलते हैं। हम राजनीति से राष्ट्रनीति को अलग करके चलने वाले लोग नहीं हैं। ये भी सच्चाई है कि अभी भी देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक राजनीति है परिवार भक्ति की और दूसरी है, राष्ट्र भक्ति की। केंद्रीय स्तर पर अलग-अलग राज्यों में हमारे यहां कुछ राजनीतिक दल हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने-अपने परिवार के हितों के लिए काम करते हैं। परिवारवादी सरकारों में परिवार के सदस्यों का स्थानीय निकाय से लेकर संसद तक दबदबा रहता है। ये अलग राज्यों में हों, पर परिवारवाद के तार से जुड़ रहते हैं। एक दूसरे के भ्रष्टाचार को ढंककर रखते हैं। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के युवाओं को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। उनके साथ हमेशा विश्वासघात किया है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज भाजपा ही इकलौती पार्टी है, जो इस चुनौती से देश को सजग कर रही है। लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने वाली ये पार्टियां, संविधान और संवैधानिक व्यवस्थाओं को भी कुछ नहीं समझतीं। ऐसी पार्टियों से आज भी हमारे कार्यकर्ता अन्याय, अत्याचार और हिंसा के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ लड़ रहे हैं।

आज देश जमीन से जुड़े तमाम अभियानों को आगे बढ़ा रहा है। सरकार के अभियानों के सारथी भाजपा के कार्यकर्ता ही हैं। ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पार्टी 'सामाजिक न्याय पखवाड़ा' शुरू करने जा रही है। आपसे आग्रह है कि इस अभियान में सक्रियता से जुड़ें। सरकार गरीबों के लिए जो योजना चला रही है, उनके प्रति देशवासियों को जागरूक करें। कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुझे जो आदेश करेगी, मैं भी उसे कार्यकर्ता के रूप में पूरी मेहनत करूंगा। आपका साथी कार्यकर्ता होने के नाते मेरी आपसे यही अपेक्षा है।

भाजपा स्थापना दिवस का दिन इस बार नवरात्रि की पंचमी तिथि भी थी। इस दिन हम सभी मां स्कंदमाता की पूजा करते हैं। हम सबने देखा है कि मां स्कंदमाता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं और अपने दोनों हाथों में कमल का फूल थामें रहती हैं। मेरी प्रार्थना है कि मां स्कंदमाता का आशीर्वाद देशवासियों पर, भाजपा के प्रत्येक कर्मठ कार्यकर्ता और प्रत्येक सदस्य पर हमेशा बना रहे। ●●●

भाजपा ने देश भर में मनाया सामाजिक न्याय पखवाड़ा

6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक हर दिन एक कल्याणकारी योजना को समर्पित किया गया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और भाजपाराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा के दूरदर्शी नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने 6 अप्रैल से 20 अप्रैल, 2022 तक देशभर में 'सामाजिक न्याय पखवाड़ा' मनाया। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस समारोह के बाद यह पखवाड़ा 6 अप्रैल, 2022 को शुरू हुआ। उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। देशभर के लगभग 18 लाख कार्यकर्ताओं ने ऑनलाइन भाषण सुना और लगभग 31 लाख कार्यकर्ताओं के घरों पर पार्टी का झंडा फहराया गया। इस पखवाड़ा के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगातार 15 दिनों तक केंद्र सरकार के गरीब हितैषी कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को मंडल और जिला स्तर तक पहुंचाया। इन 15 दिनों में हर एक दिन ऐसे ही एक अनूठे कार्यक्रम या कल्याणकारी योजना को समर्पित किया गया। सभी सांसदों और विधायकों ने भी अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। ये कार्यक्रम बूथ, मंडल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित किए गए।

आयोजन के दूसरा दिन यानी 7 अप्रैल 'आयुष्मान भारत' योजना कार्यक्रम को समर्पित रहा। इस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने देशभर में 48,561 'पीएम जन औषधि केंद्रों' का दौरा किया और लगभग 26 लाख लाभार्थियों से बातचीत की।8 अप्रैल को 'पीएम आवास योजना' को समर्पित किया गया। इस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूर्ण हो चुकी आवास योजना साइटों पर लगभग 50,600 सम्मेलन आयोजित किए और इस योजना के 23 लाख लाभार्थियों से बात की और उन्हें इस योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की।9 अप्रैल को 'हर घर जल' कार्यक्रम को समर्पित किया गया। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 'जल जीवन मिशन' की शुरुआत की थी और अब इस योजना के तहत छह करोड़ से अधिक घरों में नल से साफ पानी पहुंचाया जा चुका है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगभग 10,56,358 लाभार्थियों से बात की और देशभर में लगभग 2,28,783 मिट्टी के बर्तन वितरित किए।10 अप्रैल 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' को समर्पित था। उस दिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया, 3,563 किसान सम्मेलन का आयोजन किया और लगभग 4,61,225 किसानों से मुलाकात कर, उन्हें 'प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना', 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना', 'नीम कोटेड यूरिया' और अन्य कल्याणकारी योजनाएं के लाभों से अवगत करवाया।

13 अप्रैल को 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' को समर्पित किया गया। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसे सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।

11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगभग 8,226 स्थानों का दौरा किया और ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लगभग 38,499 अनुसूचित जाति के स्कूलों का दौरा किया और छात्रों के साथ बातचीत की।12 अप्रैल को 'टीकाकरण दिवस' के तौर पर मनाया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में अब तक भारत में 185 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक निःशुल्क वितरित की जा चुकी है। इस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने 8,753 टीकाकरण केंद्रों का दौरा किया, 12,074 लाभार्थियों से मुलाकात की और ऐसे कई लोगों से संपर्क किया जिन्होंने अभी तक कोविड-19 का टीका नहीं लिया है। उन्होंने उनसे जल्द से जल्द अपनी टीका लेने का अनुरोध किया। इन कार्यक्रमों में लगभग 28,347 जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।

13 अप्रैल को 'पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना' को समर्पित किया गया। वैश्विक कोरोना महामारी के कारण मार्च, 2020 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी और इसे सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार देशभर में 80 करोड़ लोगों को मुफ्तखाद्यान्न उपलब्ध करा रही है। इस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगभग 28,651 लाभार्थी सम्मेलन आयोजित किए और इन कार्यक्रमों में 3,83,590 लाभार्थियों ने भाग लिया।

बाबासाहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल, 1891 को हुआ था। इस वर्ष इस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने बाबासाहेब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और प्रत्येक बूथ पर 5,00,800 स्थानों पर पुष्पांजलि अर्पित की और 'सेवा कार्य' किया। लगभग 5,506 सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 4.5 लाख लोगों ने भाग लिया। इस दिन समाज के वंचित लोगों से भी कार्यकर्ताओं ने मुलाकात और बातचीत की।

15 अप्रैल का दिन अनुसूचित जनजाति कल्याण को समर्पित था। इस दिन, भाजपा कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने समाज के लिए असाधारण कार्य किया है। इसके अलावा, कार्यकर्ताओं ने अनुसूचित जनजाति समुदाय के लाभ के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों से अनुसूचित जनजाति के लोगों को अवगत करवाया। अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने 4,795 एसएचजी की बैठकें भी आयोजित कीं और लगभग 1,41,210 लोगों ने बैठकों में भाग लिया।16

छत्तीसगढ़ पखवाड़ा

■ सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत छत्तीसगढ़ के दस आकांक्षी जिलों में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मोदी जी की सरकार के मंत्रियों का प्रवास काफी उपयोगी रहा। इस क्रम में संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल का दो दिवसीय बस्तर प्रवास पर हुआ।वहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य रूप से स्वागत किया। केंद्रीय संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकारीयों की बैठक ली। श्री मेघवाल ने आकांक्षी जिलों के विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, रोजगार, अधोसंरचना आदि क्षेत्रों के अंतर्गत समीक्षा करते हुए आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। जिससे केंद्र स्तर पर सहायता के लिए पहल की जा सके। बस्तर में जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए बादल एकेडमी और कलागुड़ी का संचालन, युवा स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित थिंक बी, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संचालित ज्ञानगुड़ी, रोजगार संवर्धन के लिए बस्तर में महिला स्वसहायता समूहों के माध्यम से की जा रही पपीता और कॉफ़ी की खेती, शिक्षा के लिए मोहल्ला क्लास एवं सीख कार्यक्रम आदि के संबंध में जानकारी ली।

■ इसी अभियान के तहत दो दिवसीय प्रवास पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री श्री नित्यानंद राय बीजापुर पहुचे। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते कहा कि बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र सरकार द्वारा ठोस कदम उठाने की बात की। श्री राय ने नक्सलियों से अपील करते कहा कि वे हिंसा और हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ें। उनके लिए सरकार तमाम योजनाओं का फायदा सरकार दिलाएगी। श्री राय ने साल 2023 में छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि गोठानों के जरिए ग्रामीणों को किसी तरह का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है।

■ संचार राज्य मंत्री श्री देवू सिंह चौहान ने दंतेवाड़ा में दूरसंचार विभाग और डाक विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिलों को 1200 करोड़ के बजट में 1500 नए टावरों के साथ स्थापित किया जाएगा। इससे क्षेत्र के सभी दूरदराज के क्षेत्रों में मोबाइल कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। श्री चौहान ने दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर पर विशेष आवरण एवं दंतेवाड़ा के 16 विशेष आकर्षणों पर पिक्चर पोस्टकार्ड के संग्रह का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा की उन्नत आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत पर भारत के हर नागरिक को गर्व है।

अंत्योदय

अप्रैल का दिन असंगठित कामगारों को समर्पित था। इस दिन लगभग 6,334 असंगठित श्रमिक सम्मेलन आयोजित किए गए और लगभग 2 लाख श्रमिकों ने इसमें भाग लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने ऐसे श्रमिकों के पंजीकरण पर भी काम किया, जिनका आज तक पंजीकरण नहीं हुआ है।

17 अप्रैल को वित्तीय समावेशन गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगभग 3,04,243 'जन धन योजना' के लाभार्थियों से मुलाकात की और विभिन्न बीमा योजनाओं के तहत लगभग 3,42,744 लोगों कापंजीकरण करवाया। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 'जन धन से जन सुरक्षा' के मंत्र के तहत सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है। ऐसे ही प्रधानमंत्री बीमा योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब 'अटल पेंशन योजना' के तहत कुल लाभार्थी की संख्या 4.01 करोड़ से अधिक, 'प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना' के तहत 12.66 करोड़ से अधिक और 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के तहत कुल 28.19 करोड़ लाभार्थी पंजीकृत हैं। 18 अप्रैल 'स्वच्छ भारत मिशन' को समर्पित था। इस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित राष्ट्रीय नायकों की प्रतिमाओं की सफाई की। इसके अलावा, 54,562 स्थानों पर नदियों, मंदिरों, तालाबों आदि की सफाई जैसे कार्यक्रम चलाये और 1,07,133 'स्वच्छता सैनिकों' को इस अवसर पर सम्मानित किया गया।19 अप्रैल को 'पोषण अभियान' दिवस के तौर पर मनाया गया। इस दिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने गांवों में 15,920 पीएचसी और आंगनवाड़ी केंद्रों का दौरा किया और 1,26,568 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। उन्होंने पोषण पर जन जागरूकता अभियान चलाए और इन केंद्रों में 4,41,648 भोजन के पैकेट वितरित किए।

सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतिम दिन 'अमृत महोत्सव' से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 3,597 अभिनंदन सभा का आयोजन किया गया जिसमें 7,441 स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के अंतिम दिन लगभग 1,43,185 भाजपा कार्यकर्ताओं ने समाज, गरीबों और आम लोगों के कल्याण के लिए पिछले आठ वर्षों के दौरान मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को लेकर जागरूकता फैलाई।

■ छत्तीसगढ़ दौरे पर आए केंद्र के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने दो दिवसीय प्रवास के दौरान विभागीय अधिकारियों, आमजन,भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। सामाजिक समरसता पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत वो आकांक्षी जिलों का कर रहे दौरा कर रहे हैं।केंद्रीय मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं से आम आदमी को सहुलियतें देने का काम कर रही है।रायपुर में श्री वर्मा ने स्वच्छता अभियान के तहत साहू पारा में तालाब की सफाई की।इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी और संजय श्रीवास्तव मौजूद रहे। यहां से केंद्रीय मंत्री कांकेर के लिए रवाना हो गए। श्री वर्मा ने कांकेर अंतर्गत गांधीग्राम कुलगांव में महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न आर्थिक गतिविधियोंकिया। इस दौरान सांसद श्री मोहन मण्डावी, पूर्व सांसद श्री विक्रम देव उसेण्डी, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मारकोले, सतीश लाटिया, जनपद अध्यक्ष श्री रामचरण कोर्राम, श्री भरत मटियारा, श्री बृजेश चौहान, श्री बिरेन्द्र श्रीवास्तव, जनपद सदस्य श्री राजेश भास्कर, श्री रमाशंकर दर्रो, ग्राम पंचायत के सरपंच श्री कमलेश पदमाकर, कलेक्टर श्री चन्दन कुमार, जिला पंचायत सीईओ श्री सुमित अग्रवाल सहित ग्रामीणजन उपस्थित थे।

■ केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण केंद्रीय राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे कोरबा पहुंचे। कोरबा पहुंचे मंत्री श्री चौबे ने जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों सांसद,विधायक, पार्षद,महापौर, जिला पंचायत/ जिला के अध्यक्ष,सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों साथ समीक्षा बैठक की। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के कार्यालय पहुचे जहां उनके साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री अमर अग्रवाल भी थे।भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष डॉ राजीव सिंह ने शॉल श्रीफल व पुष्पगुच्छ भेंट कर मंत्री चौबे का स्वागत किया। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा के समस्त पदाधिकारियों ने महामाला से मंत्री श्री चौबे का स्वागत किया।

■ महासमुंद में केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें नियंत्रण में रहें। इसीलिए केंद्र सरकार ने पिछले साल पेट्रोल और डीजल पर से एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी थी।उन्होंने कहा, 'छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल पर वैट 24 फीसदी है। अगर इसको घटाकर 10 फीसदी कर दिया जाए तो कीमतें अपने आप कम होंगी और मांग बढ़ेगी। हालांकि, 10 फीसदी वैट भी बहुत अधिक है।'

■ केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉ महेंद्र नाथ पाण्डेय इस अभियान के तहत नारायणपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंनें आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत कलेक्टोरेट के सभाकक्ष में संबंधित विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री महेंद्र पांडेय ने जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुपोषण, पेयजल अधोसंरचना, विद्युत व्यवस्था एवं वित्तीय समावेशन सहित अन्य क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्हें नारायणपुर के अबूझमाड़ आदिवासियों के बच्चों द्वारा मलखंब का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला।

■ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सामजिक न्याय पखवाड़ा के तहत राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट में अफसरों की एक बैठक ली और केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कुपोषण, शिक्षा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और केंद्रीय योजनाओं को लेकर कलेक्टर और अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी को विकास पर ध्यान देना चाहिए। योजनाओं पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधा के साथ ही अन्य योजनाओं का क्रियान्वन समुचित तरीके से होना चहिए।

■ केंद्रीय जनजातीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह इस अभियान के तहत सुकमा पहुची। उन्होंने जगदलपुर में भाजपा के सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी योद्धा शहीद गुंडाधुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जगदलपुर में शहीद गुंडाधुर संग्रहालय बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए 25 करोड़ वे स्वयं अपने फंड से देंगी। ●●●

खैरागढ़ का जनादेश विनम्रतापूर्वक स्वीकार, मतदाताओं का सम्मान, धन्यवाद : भाजपा

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि भाजपा जनादेश का सम्मान करती है। खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने विजयी प्रत्याशी कोबधाई दी।श्री साय ने कहा कि जनता के हित में भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ भाजपा लगातार संघर्षरत रहेगी। भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस घोषणा पत्र के सभी 29 बिंदुओं पर अमल के लिए इसी क्षण से भूपेश बघेल सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने तैयार हैं। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं की संघर्ष क्षमता को नमन करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिन्होंने सत्ता और उसके चाटुकार प्रशासन की तानाशाही तथा कांग्रेस के कारनामों का जमकर मुकाबला किया।

प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री साय ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अनैतिकता की हद पार कर दी। कांग्रेस ने शासन-प्रशासन का खुला दुरुपयोग किया। यह चुनाव कांग्रेस ने नहीं बल्कि प्रशासन ने लड़ा। जिसमें सरकारी मशीनरी का सौ फीसदी दुरुपयोग किया गया है। यह कांग्रेस के हथकंडों और अनैतिक दुष्प्रचार की जीत तथा लोकतंत्र की पवित्रता पर डाका है। उन्होंने कहा कि अगले साल होने वाले चुनाव में पूरे प्रदेश से कांग्रेस की अलोकतांत्रिक तरीके अपनाकर जनता को छलने वाली सरकार के सफाये के लिए भाजपा के कार्यकर्ता संघर्ष करेंगे।प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने पहले जनता को झांसा देकर सत्ता हासिल की। उसके बाद जनता के साथ हर मुद्दे पर वादाखिलाफी की। यही झाँसेबाजी खैरागढ़ उपचुनाव में भी की गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के सभी बिंदु उसकी सरकार की विफलता का दस्तावेज हैं। साढ़े तीन साल तक कांग्रेस की सरकार ने अगर कोई काम किया होता तो खैरागढ़ उपचुनाव में 29 वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती।

प्रदेश भाजपाध्यक्ष श्री साय ने कहा कि इस चुनाव में कांग्रेस ने अनैतिकता की हद पार कर दी।

अब प्रियंका स्पष्ट करें कि बेटी लड़े या भूपेश की दबंगई के सामने चुप हो जाये- शालिनी

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि जब वे कबूल कर रहे हैं कि एक दुखी लड़की को उन्हें अपनी पीड़ा बताते समय नहीं डांटना चाहिए था तो वे उनकी बदतमीजी सबके सामने लाने को साजिश कैसे बता सकते हैं। यह कोई साजिश नहीं, एक दुखियारी बेटी के प्रति मुख्यमंत्री के दुर्व्यवहार और महिलाओं के अपमान का कड़वा सच है। महिला सशक्तिकरण का ढोंग करने वाले भूपेश बघेल का वास्तविक चेहरा है, जो सामने आया है। भूपेश बघेल को बहानेबाजी दिखाने की बजाय अपने इस निम्न स्तर के व्यवहार के लिए छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। यदि उन्होंने मातृ शक्ति के अपमान पर क्षमा नहीं मांगी तो उन्हें इसकी कीमत चुकाने तैयार रहना चाहिए। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि भाजपा महिला मोर्चा महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए भूपेश बघेल की अत्याचारी सरकार का मुकाबला करने तैयार है। भूपेश बघेल नारी के सम्मान की रक्षा नहीं कर सके। साढ़े तीन साल से छत्तीसगढ़ में महिलाओं की इज्जत खतरे में है। हर रोज दुष्कर्म और महिला उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। बेहद शर्मनाक घटना है कि खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी महिला के अपमान और उत्पीड़न की कड़ी में शामिल हो गए।

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान चार राज्यों में भाजपा की जीत की बधाई दी। साथ ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की तिथि बढ़ाने पर उन्होंने आभार भी व्यक्त किया।

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा मातृशक्ति का अपमान किए जाने के विरोध में पूरे प्रदेश भर में पुतला दहन किया।

केंद्र सरकार ने 2021-22 में खाद्य सब्सिडी के लिए जारी किए 2,94,718 करोड़ रुपये

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खरीद कार्यों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत खाद्यान्न के निर्बाध वितरण के लिए खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने 2,92,419.11 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान के मुकाबले डीसीपी और गैर-डीसीपी दोनों गतिविधियों के तहत भारतीय खाद्य निगम तथा राज्य सरकारों को खाद्य सब्सिडी के लिए 2,94,718/- करोड़ रुपये जारी किए हैं।

खाद्य सब्सिडी हेतु दी गई यह राशि 2020-21 के दौरान जारी खाद्य सब्सिडी का लगभग 140% और 2019-20 के दौरान उपलब्ध कराई गई खाद्य सब्सिडी का करीब 267% है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 3,04,879/- करोड़ रुपये के शुद्ध आवंटन के मुकाबले 3,04,361 करोड़ रुपये खर्च करके 99.83% व्यय हासिल किया है।

केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए तत्पर रहता है कि उसकी योजनाओं का लाभ समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों तक पहुंचे। इस मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अनुसूचित जातियों के लिए लगभग 24,000/- करोड़ रुपये, अनुसूचित जनजातियों हेतु 12,000/- करोड़ रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र को 400/- करोड़ रुपये से अधिक धनराशि जारी की है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत 80 करोड़ से अधिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो की दर से अतिरिक्त खाद्यान्न उनकी मासिक पात्रता के अलावा भी मुफ्त में जारी किया गया है।

खाद्य सब्सिडी हेतु दी गई राशि 2019-20 के दौरान उपलब्ध कराई गई खाद्य सब्सिडी का करीब 267% है।

कार्यकर्ताओं से रूबरू होने बूथ तक पहुंचे श्री बृजमोहन अग्रवाल व श्रीचंद सुंदरानी

कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत आज भाजपा रायपुर शहर के विभिन्न बूथों में भाजपा नेताओं ने कार्यकर्ता और जनता से मुलाकात की। पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल काली बाड़ी चौक, मौलाना अब्दुल रउफ वार्ड के बूथ क्रमांक 43 में पहुंचे । जनता ने उनसे प्रधानमंत्री आवास व 5 किलो अतिरिक्त राशन न मिलने की शिकायत की । इस अवसर पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में जनहित के सारे कार्य रुके पड़े हैं और इसकी जिम्मेदारी भूपेश सरकार की है। उन्होंने सरकार को जनहित के कार्य शीघ्र कराने अन्यथा अंजाम भुगतने की चेतावनी दी । भाजपा रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी पंडरी स्थित गुरु गोविंद सिंह वार्ड के बूथ क्रमांक 84 जगन्नाथ नगर पहुंचे । उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ की मजबूती के लिए कार्य करने का आवाहन किया। उन्होंने जनता से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में विकास के नए आयाम गढ़े । भारत के सभी विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थान आज छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की देन है। उन्होंने भूपेश सरकार की नाकामी बताते हुए कहा कि पिछले 3 सालों में उन्होंने विकास के लिए प्रयास तक नहीं किए। वार्ड के नागरिकों ने उन्हें सफाई व्यवस्था न होने व पेयजल की समस्याओं से अवगत कराया।

वादा तोड़ छत्तीसगढ़ को बार में बदल डालने का इरादा : भाजपा

छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री धरम लाल कौशिक ने कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों के लिए रियायती दर पर होटल बार लायसेंस प्रदाय किए जाने का निर्णय लिए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वादा तोड़ छत्तीसगढ़ को बार में बदल डालने का इरादा, हद कर दी आपने। हाथ में गंगाजल लेकर छत्तीसगढ़ में शराब बंदी लागू करने का वादा कर सत्ता में आने वाली भूपेश बघेल सरकार ने साढ़े तीन साल में यह वादा पूरा करने की जगह राज्य को शराब का गढ़ बना दिया है। यह सरकार शराब को वैध अवैध कमाई का जरिया बना चुकी है।

गंगाजल लेकर शराब बंदी करने का वादा करने वाली भूपेश सरकार राज्य को शराब का गढ़ बना दिया है

श्री कौशिक ने कहा केंद्र पर आरोप लगाने वाले इसे 30 साल की लीज पर दे रहे है तो ये निजी लोगो को संपति बेचना नही तो क्या है?

श्री कौशिक ने कहा कि हद तो यह है कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने और पर्यटकों की सुविधा में वृद्धि के नाम पर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अधीन 26 इकाइयों को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इनमें शराब बेची जायेगी। भूपेश बघेल सरकार बेरोजगार युवाओं को यही रोजगार थमाना चाहती है। राज्य के युवाओं को न तो रोजगार मिला और न ही बेरोजगारी भत्ता। कांग्रेस की सरकार ने राज्य के युवाओं को पहले तो गोबर बटोरने का रोजगार दिया और अब शराब परोसने के काम पर लगाना चाहती है।

राज्य की कांग्रेस सरकार ने पांच लाख परिवारों से छल किया: भाजपा

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने राज्य कर्मचारियों का पांच फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पांच लाख परिवार के 25 लाख लोगों के भरोसे को तोड़ा है। उनके साथ छल किया है। महंगाई भत्ता 17 प्रतिशत की जगह पांच फीसदी बढ़ाना राज्य कर्मचारियों के साथ अन्याय है। राज्य सरकार को केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता देने की मांग करते हुए श्री साय ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने केंद्र के मुकाबले 12 फीसदी कम महंगाई भत्ता देना तय किया है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को सिर्फ पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने बमुश्किल तैयार हुई है। यह वृद्धि ऊंट के मुंह में जीरा वाली स्थिति के जैसी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के कर्मचारियों को सपने दिखाए। उनसे किये गए वादे पूरे करने की बजाय उनका शोषण कर रहे हैं। महंगाई भत्ता बढ़ाने की कर्मचारियों की लंबे समय से की जा रही मांग को लटकाते रहे। कहा गया था कि जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। अब यह खुशखबरी है या राज्य की सेवा में लगे कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिए हताश निराश कर देने वाला फैसला है कि हर मौके बेमौके केंद्र पर दोष मढ़ने वाले मुख्यमंत्री ने अपने कर्मचारियों का मामूली सा भत्ता बढ़ाया है। जबकि कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद थी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि अब मुख्यमंत्री बताएं कि केंद्र सरकार के वित्त पोषण की दम पर राज्य की जनता और राज्य कर्मचारियों का शोषण करने वाली सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर क्यों नहीं दिया।

सांसद सुश्री सरोज पांडेय ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव से मुलाक़ात की। उन्होंने प्रदेश के रेलवे से सम्बंधित सभी मांगों और मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की।

भाजपा बिलासपुर संभाग की बैठक ली प्रदेश सह प्रभारी श्री नितिन नबीन ने। इस अवसर पर संगठन महामंत्री श्री पवन साय, नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक, प्रदेश महामंत्री श्री भूपेंद्र सवन्नी, श्री कृष्णा राय भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री का यात्रा मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर है: कौशिक

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरे प्रदेश में जिस तरह से यात्रा कर रहे हैं उनका हर दृश्य मुन्ना भाई एमबीबीएस फिल्म की तरह है। जब प्रदेश में गर्मी की छुट्टी घोषित की गई है,तब बच्चें स्कूल कैसे जा रहे हैं? सारा चीज जब प्रशासन को पता है जिसकी तैयारी आगे से ही कर ली जाती है। जहां जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जा रहे है। वहां की तस्वीर कुछ और ही है। केवल इवेंट मैनेजमेंट कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केवल वाहवाही लूट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है वहां किसी से छिपी नहीं है।उस पर मुख्यमंत्री बघेल कुछ भी नहीं बोलते हैं और केवल मात्र सांस्कृतिक रूप से भावनात्मक बातें कर सबको भ्रमित कर रहे हैं। राज्य के युवा बेरोजगारी भत्ता की मांग कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री उस पर चर्चा करने से बचते है। केवल मात्र प्रायोजित कार्यक्रमों में ही वाहवाही लूटने में व्यस्त है। एक छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई कर रहें हैं और जिम्मेदार अधिकारियों पर कुछ भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रदेश के मंत्री टीएस सिंहदेव खुद की ही सरकार को आईना दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के बीच जो प्रतिस्पर्धा चल रहा है वह किसी से छिपा नहीं है और कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र समिति के प्रमुख मंत्री टीएस सिंहदेव ने खुद ही कहा है कि जो वादे किए थे हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

प्रदेश में गर्मी की छुट्टी घोषित की गई है,तब बच्चें स्कूल कैसे जा रहे हैं?

जब मंत्री ने कहा कलेक्टर भ्रष्ट है तो सुना नहीं, अब पटवारी को सस्पेंड कर तोपचंद बन रहे हैं भूपेश: भाजपा

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छोटे-मोटे अफसरों और कर्मचारियों पर निलंबन की कार्रवाई करके प्रदेश की जनता को आखिर क्या बताना चाहते हैं? जबकि उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार पर उनकी आंखें रंगीन चश्मे चढ़ा लेती हैं। अभी हाल ही विधायक के भ्रष्टाचार पर उंगली उठाने वाले युवा आयोग के सदस्य को 6 साल के लिए कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी कांग्रेसियों को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेगा वह अनुशासनहीन माना जाएगा। कांग्रेस विरोधी माना जाएगा और भूपेश बघेल का भी विरोधी माना जाएगा। दूसरी बात यह कि जब उनके ही मंत्रिमंडलीय सहयोगी ने कोरबा कलेक्टर को भ्रष्ट बताया था तो भूपेश बघेल ने अपने ही मंत्री के कथन पर कोई एक्शन नहीं लिया। अब छोटे-मोटे कर्मचारियों को सस्पेंड करके भूपेश बघेल तोपचंद बन रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश की जनता को भ्रमित करने के लिए तरह-तरह के स्वांग रचते हैं। वह भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहे हैं। प्रदेश में पूरी तरह अराजकता और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छत्तीसगढ़ अपराध गढ़ बन गया है। तरह-तरह के माफिया सरकार के राजनीतिक संरक्षण में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। सरकार का पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार के अधीन चल रहा है। बड़े-बड़े घोटालेबाज रिटायरमेंट के बाद भी सरकार की अनुकंपा पर जमे हुए हैं और जिम्मेदार पदों पर काम कर रहे हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को नए-नए कारनामे करने के लिए अवसर दिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में यह सरकार किसी काले दाग से कम नहीं है। कांग्रेस की तो संस्कृति में ही भ्रष्टाचार रचा बसा हुआ है लेकिन देश भर के कांग्रेसियों के बीच भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचार के मामले में सबसे आगे निकल चुकी है।

महिलाओं की रोजी-रोटी पर लात मार रही है प्रदेश सरकार : महिला मोर्चा

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने आज राजभवन जाकर महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपी। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से रेडी टू ईट निर्माण का कार्य महिला स्व सहायता समूह को दिए जाने के संबंध में चर्चा किया। माननीय उच्च न्यायालय ने रेडी टू ईट निर्माण को लेकर 287 याचिकाओं को खारिज करते हुए इस पर प्रदेश सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है। भाजपा महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि हम सभी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार अब अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए यह कार्य पुनः महिला स्व सहायता समूह को सौंपे इस मांग को लेकर भी राज्यपाल महोदय से चर्चा की। एक ओर प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिला सशक्तिकरण की बातें करते है तथा दूसरी ओर उन्हीं महिलाओं के हाथों से काम छीनकर उन्हें बेरोजगार करने का काम भी कर रहे है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण हेतु महिला समूह का गठन करके उन्हें विभिन्न योजनाओं के तहत भिन्न-भिन्न कार्य सौंपा है तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार महिला स्व. सहायता समूहों के काम को छीन कर न केवल उन्हें बेरोजगार कर रही बल्कि उनके पेट पर लात मार रही है। अगर प्रदेश की सरकार महिलाओं का सच में भला चाहती है तो वह रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण का कार्य पुनः महिला स्व. सहायता समूहों को सौंपे। यही महिलाओं के हित में होगा। इस अवसर पर विशेष रुप से श्रीमती शालिनी राजपूत डॉक्टर ममता साहू विभा अवस्थी सीमा साहू सोना वर्मा संध्या तिवारी डॉक्टर किरण बघेल बिंदु महेश्वरी सविता चंद्राकर चेतना गुप्ता संगीता जैन मिली बनर्जी ललिता वर्मा सरला वर्मा अमेरिका वर्मा रानी पटेल प्रमिला साहू रुकमणी तिवारी और भारी संख्या में रायपुर शहर एवं रायपुर जिला ग्रामीण की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता उपस्थित थे

शालिनी राजपूत का सवाल क्या यही है प्रदेश सरकार का महिला सशक्तिकरण अभियान?

राज्य सरकार ने जिन 17 हजार महिलाओं से रोजगार छीना उनके लिए क्या व्यवस्था की है? : विष्णुदेव

छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए कहा है कि रेडी टू ईट मामले में सरकार के फैसले को न्यायालय ने असंवैधानिक नहीं माना है लेकिन अब राज्य सरकार बताये कि इस योजना के तहत स्व सहायता समूह की करीब 17- 18 हजार महिलाओं को रोजगार देने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है? यह छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि ऐसी संवेदनहीन सरकार काबिज है जिससे पीड़ित महिलाओं को रोजगार के लिए न्यायालय जाना पड़ता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि ये महिलाएं रेडी टू ईट योजना में स्व सहायता समूह के रूप में रोजगार करके परिवार का भरण पोषण कर रही थीं। सरकार ने इन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराए बिना ही इनका रोजगार छीन लिया तो अब इस सरकार का यह नैतिक दायित्व है कि एक लाख लोगों के जीवन यापन पर जो दुष्प्रभाव पड़ा है, उससे बचाने के लिए वैकल्पिक रोजगार दे।

भाजपा मोर्चा अध्यक्ष व मोर्चा प्रभारियों की बैठक मे भाजपा प्रदेश प्रभारी श्रीमती डी पुरुंदेश्वरी, सह प्रभारी श्री नितिन नबीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री श्री पवन साय, व नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक मौजूद थे।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की प्रदेश कार्यसमिति बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संपन्न हुई। राष्ट्रीय संयोजक श्री राजेंद्र फड़के ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देशभर में बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए एवं उनको प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान तेजी से चलाया जा रहा है।

किसानों को बर्बरता से कुचल रही है कांग्रेस

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि नया रायपुर प्रभावित किसान कल्याण समिति द्वारा अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत 03/01/2022 से अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन कर रहे है, परन्तु भूपेश सरकार तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों की मांगों को पूरा करने के बजाय उनके ऊपर लाठीचार्ज कर बर्बरतापूर्ण कार्यवाही कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण आंदोलनरत किसानों पर राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ प्रवास के समय आंदोलनरत किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कर किसानों के आंदोलन को दबाने व कुचलने का प्रयास किया गया। दूसरी बार अपनी मांग पत्रों को लेकर ज्ञापन सौंपने प्रमुख सचिव के पास मंत्रालय जा रहे किसानों पर पुनः लाठीचार्ज कर मारपीट कर पुलिसिया कार्यवाही किया गया। जिसमें स्थानीय निवासी ग्राम बरौदा के सियाराम पटेल जी का धरनास्थल पर ही निधन हो गया। किसान सियाराम पटेल के मृत्यु के बाद भी आंदोलन जारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी झूठे वादों से बचने के लिए बुढ़ातालाब धरना स्थल पर विद्युत कर्मचारियों के ऊपर पुलिसिया कार्यवाही बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। जिसमें कई कर्मचारियों को गंभीर चोट भी आयी है। उसी दिन 23/04/2022 को धरना स्थल पर सो रहे किसानों के ऊपर मध्य रात्रि को अचानक पुलिसिया कार्यवाही किया गया। वहीं किसानों की गिरफ्तारी कर उन्हें बलपूर्वक हटाया तथा बाकि आंदोलनरत किसानों को तितर बितर करने लाठी व बल का प्रयोग किया गया। तत्पश्चात धरना स्थल पर लगे हुए पंडाल, खाना बनाने के बर्तन, चावल, सामानों पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया तथा सामानों को जब्त कर थानों में रखा गया व बंदी बनाए गए किसानों को कभी राखी थाना तो कभी जेल परिसर तो कभी माना थाने घुमाकर चकमा देते हुए उनके ऊपर पुलिसिया कार्यवाही किया गया। अन्य आंदोलनरत कर्मचारियों व मितानिनों के ऊपर अत्याचार कर बलपूर्वक पुलिसिया कार्यवाही किया गया। इसी तरह भूपेश सरकार आंदोलनरत किसानों, कर्मचारियों एवं मितानिनों के ऊपर पुलिसिया डर दिखाकर आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया।

संविदा कर्मचारियों को नृशंसता से पिटवाना कांग्रेस सरकार की कायरता हैः भाजपा

प्रदेश की राजधानी में पिछले कई दिनों से अपनी मांगो को लेकर प्रदर्शन कर रहे संविदा कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने दुःख व्यक्त किया है। श्री साय ने कहा प्रदेश के युवाओं को कांग्रेस सरकार द्वारा पीटा जाना बेहद दुर्भाग्यजनक है। गांधीवादी तरीके से कांग्रेस सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराना ,सरकार द्वारा किए वादों को उन्हे याद दिलाना कोई पाप या अपराध नही जो पुलिस से उन्हे बर्बरता से पिटवाया गया। श्री साय ने कांग्रेस सरकार से पूछा है क्या प्रदेश के युवा गुंडे थे जो इन्हें पीटा गया इनकी गलती क्या थी? लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन को कुचलने का यह बेहद शर्मनाक तरीका है। श्री साय ने कांग्रेस सरकार से कहा कि वो चुनाव से पहले इन युवाओं से किए अपने वादे को याद करे इन्हे 10 दिनों में नियमित करने का वादा किया गया था स्वयं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व टीएस बाबा ने संविदा कर्मचारियों से यह वादा किया था आज सरकार बने 1000 से ज्यादा दिन हो चुके है।राज्य सरकार को उनकी मांगे पूरी करनी चाहिए लेकिन वह उनके साथ बर्बरता से पेश आ रही है यही कांग्रेस का असली चरित्र है।

पंकज झा.

एक अघोषित आपातकाल से गुजरता छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने बढ़ते जनाक्रोश को कुचलने के लिए प्रदेश में धार्मिक रैलियों, धरना-प्रदर्शन, धार्मिक आयोजनों आदि पर कड़े प्रतिबन्ध लगाए हैं।

राजनीति भी इस मामले में अभिशप्त है कि वहां भी इतिहास दुहराये जाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग अभी उस इतिहास को याद कर रहे हैं जब सत्ता के नशे में तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सभी नागरिक अधिकारों को ख़त्म करते हुए देश पर आपातकाल थोप दिया था। अरसे बाद छत्तीसगढ़ में आयी कांगेस की सत्ता फिर से उसी तरह का आपातकाल लगाने की तरफ अग्रसर है। फिलहाल ऐसा अघोषित आपातकाल जिसमें असहमति के लिए कोई स्थान नहीं हो, जहां विपक्ष की आवाज़ दबाने की भरसक कोशिश की जाय। जहां भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ऐसा ही पनाह मांगें जैसा घोषित आपातकाल के दौर में मांग रही थी। जहां रस्म चलने सी लगी है कि कोई न सर उठा के जीये।

मोटे तौर पर कहा यह जा सकता है कि दर्जनों असंभव सा दिखते लोक-लुभावन घोषणाओं को करके कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता में तो आ गयी लेकिन साढ़े तीन साल गुजरने के बाद जब अब प्रदेश की जनता का धैर्य लगभग चुक सा गया है और समाज का हर वर्ग बुरी तरह आक्रोशित और आन्दोलन रत है, तब कांग्रेस सरकार खुद को उसी तरह फंसा महसूस कर रही है जैसा 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रतिकूल फैसले के बाद तब की पीएम इंदिरा गांधी महसूस करने लगी थी। अपने ही बड़बोलेपन और वादाखिलाफी के जंजाल में फँसी भूपेश बघेल की सरकार ने अंततः तरीका भी वही निकाला जैसा इंदिरा गांधी ने निकाला था। भूपेश सरकार ने एक तुगलकी आदेश जारी कर प्रदेश भर के सभी निजी, सार्वजानिक, धार्मिक, राजनीतिक, अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तावित आयोजनों पर, जिसमें भीड़ आती हो, उसे रोकने के लिए 19 बिन्दुओं की शर्तें लगाई हैं। उन सभी शर्तों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने का फरमान निकाला गया है।

मोटे तौर पर कहा यह जा सकता है कि दर्जनों असंभव सा दिखते लोक-लुभावन घोषणाओं को करके कांग्रेस छत्तीसगढ़ की सत्ता में तो आ गयी लेकिन साढ़े तीन साल गुजरने के बाद जब अब प्रदेश की जनता का धैर्य लगभग चुक सा गया है और समाज का हर वर्ग बुरी तरह आक्रोशित और आन्दोलन रत है।

ये ऐसी शर्तें हैं जिसका पूरी तरह पालन कर कोई भी बड़ा धार्मिक/ राजनीतिक/ सामाजिक आयोजन संभव ही नहीं है। इसका सीधा अर्थ यह है कि सरकार यह चाहती है कि जन संगठनों के विरोध प्रदर्शनों को, असहमति की आवाज़ को, विपक्ष को, धार्मिक भावनाओं को, अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल दे।

इस आदेश में उल्लिखित शर्तों के बिंदु 8,12,13,14,15,18 और 19 में खासकर ऐसे प्रावधान हैं जो सीधे तौर पर हमारे संवैधानिक मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। इनमें कुछ को पढ़ कर ऐसा लगता है मानो कांग्रेस यह मान बैठी है कि ऐसे सभी आयोजनों के आयोजक तब तक अपराधी हैं जब तक कि वे निरपराध साबित न हो जायें। और खुद को निरपराध साबित करने की जिम्मेदारी भी खुद आयोजक की है। शासन उन्हें ऐसा संदिग्ध मानेगा, मानो वे आदतन अपराधी हों। वास्तव में इस सनक भरे आदेश के तहत कांग्रेस सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को और खुद के खिलाफ असहमति का आवाज़ बुलंद करने वाले समूहों-दलों को चुन-चुन कर निशाना बनाने की फिराक में है। इसके तहत वास्तव में केवल कांग्रेस को ही अभिव्यक्ति एवं प्रदर्शन का अधिकार रह जाएगा। इस आदेश के आने के बाद कांग्रेस ने खुद केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, घेराव आदि किया लेकिन, उसे ऐसी कोई अनुमति लेने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। जाहिर है इससे केवल कांगेस प्रेरित स्वेच्छाचारिता और दमन को बढ़ावा मिलेगा। वह इस आदेश की आड़ में टार्गेटेड हमले करेगी।

आखिर ऐसे तुगलकी आदेश की ज़रूरत हुई क्यों? इसका जवाब कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में निहित है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के आने में एक बड़ी भूमिका उस पार्टी द्वारा लाये गए 'जन घोषणा पत्र' की भी मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि अगर अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने दर्जनों लोक-लुभावन और असंभव सा दिखते वादे नहीं किये होते, तो डेढ़ दशक की भाजपा सरकार को यहां से उखाड़ पाना संभव नहीं था। कांग्रस के पास क्योंकि हमेशा सबसे अधिक संकट भरोसे का रहता है, उस पर जनता अब अमूमन विश्वास करने को तैयार नहीं होती, इसे समझते हुए पार्टी ने छग की धर्मप्राण जनता को भरोसे में लेने विधानसभा चुनाव के समय धार्मिक आस्था का दाव चला, उसने गंगाजल उठा कर सार्वजनिक कसम लिया था कि वह वादों को पूरा करेगी। यह दाव चल निकला था कांग्रेस का, और अंततः एक लम्बे शासन को समाप्त कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में नयी सरकार का गठन हुआ।

लेकिन सत्ता में आने के बाद अपने लगभग सभी वादों से मुकरते हुए कांग्रेस ने एक तरह से उन सभी चीज़ों को नज़रंदाज़ किया जो उसने कहा था। अनेक मामलों में तो उसने अपने कहे के ठीक विपरीत आचरण भी किया। जैसे शराबबंदी का वादा किया था लेकिन अपने कहे के ठीक उलट उसने देश में पहली ऐसी सरकार का खिताब हासिल किया जिसने बाकायदा शराब की सरकारी तौर पर होम डिलीवरी की प्रणाली भी शुरू की है। अब तो इससे भी आगे जा कर सभी सरकारी मोटलों-होटलों में बार बनाने के लिए अभियान जैसा चलाने का फैसला कैबिनेट में लिया है। गंगाजल हाथ में लेकर कर शराबबंदी का वादा करने वाली कांग्रेस यहां शराब की वैध-अवैध कमाई से कोरोना काल में भी अपना खजाना भरती रही। इसी तरह मंडी शुल्क ख़त्म करने का वादा था लेकिन वादे के उलट उसे भी डेढ़ सौ प्रतिशत बढ़ा दिया। किसानों को क़र्ज़ मुक्त करने का वादा था लेकिन उलटे उसने समूचे प्रदेश को ही कर्ज़दार बना दिया। मात्र तीन साल में ही उसने पिछले पन्द्रह वर्ष से अधिक का क़र्ज़ ले लिया। दो साल का धान का बकाया बोनस नहीं दिया। दस लाख युवाओं को ढाई हज़ार बेरोजगारी भत्ता से साफ़ मुकर गयी, दस लाख युवाओं को रोजगार भी देने का तो मज़ाक ही बना दिया जब कहा कि गोबर चुन कर युवा 30 हज़ार करोड़ कमाएंगे। आंगनवाडी में काम करने वाली महिलाओं के लिए अनेक घोषणाएं थी लेकिन वहां भी एक निजी कम्पनी को लाभ पहुचाने 17 हज़ार महिलाओं की रोजी-रोटी छीन ली। प्रदेश में सभी अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने का भरोसे दिलाया था लेकिन उनके भरोसे से खेलते हुए कांग्रेस ने उनकी छंटनी शुरू कर दी। यहां तक कि कोरोना के वैश्विक आपदा के समय जिन छत्तीसगढ़ी अस्थायी कर्मचारियों ने जान हाथ में ले कर संक्रमित बीमारों की सेवा की, उन्हें भी हालात ज़रा सामान्य होते ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।

कांग्रेस के ऐसे विश्वासघातों की सूची इतनी लम्बी हो गयी है जिसके कारण समूचे प्रदेश के हर वर्ग में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। पिछले लगभग साल भर से समाज का लगभग हर वर्ग सड़क पर है, जबकि कांग्रेस आंदोलनकारियों के उत्पीड़न की एक से एक मिसाल प्रस्तुत कर रही है। कहीं प्रदर्शनकारियों को पुलिस के जूते से रौंदा जा रहा है, मुक्कों से पीटा जा रहा तो कहीं किसान और युवा आत्महत्या कर रहे हैं। सीएम निवास के सामने भी आत्मदाह की घटना सामने आयी तो आन्दोलन के दौरान किसान की मौत भी हो गयी। अन्य प्रदेश में चुनावी लाभ के लिए करोड़ों का बिना जांच मुआवजा बांट आये सीएम बघेल ने अलबत्ता किसी की खोज खबर तक लेना मुनासिब नहीं समझा। मुआवजा के लिए भी जांच की बात कर मामलों को रफा दफा कर दिया। बावजूद इसके प्रदर्शनकारियों के हौसलों को वह तोड़ नहीं पायी। गोलियां चलाती रही सरकार और आदिवासीगण सैकड़ों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय कर रायपुर पहुंचते रहे। लेकिन अब क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है तो कांग्रेस अब ऐसे विरोध प्रदर्शनों को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है।

कांग्रेसी आपातकाल के खिलाफ पूर्व में भी आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ कर जैसे देश ने जीत हासिल की थी, उसी तरह का यह विषय भी प्रदेश के लोगों के मौलिक अधिकार, उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। कांगेस के इस फितूर से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि सिविल सोसाइटी को, नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहना होगा।

इस आदेश में सबसे आपत्तिजनक और असंवैधानिक यह है कि आयोजकों से हलफनामा लिया जा रहा है कि आयोजन के दौरान किसी भी तरह के कथित उल्लंघन होने पर सीधे उन पर कानूनी कार्यवाही होगी। मतलब अब प्रदेश में हर कार्यक्रम अंततः शासन के रहमोकरम का मुहताज रहेगा। जब भी शासन का मन होगा वह किसी न किसी शर्त के उल्लंघन के आरोप में आयोजकों को जेल में डाल देगी। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती रहेगी। यहां तक कि जान-बूझकर किसी आयोजन में अशांति पैदा कर भी उसके आयोजकों को जेल भेजा जा सकता है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास में बिना घोषित किये हुए ऐसा आपातकाल लगा देने का शायद अन्य कोई उदाहरण नहीं होगा। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक कहते हैं – "आश्चर्य यह है कि विपक्ष में रहते हुए इन्हीं आंदोलनकारियों के पास जा-जा कर समर्थन के लिए हाथ फैला भूपेश बघेल आज यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन सत्ता के मद में अब इनकी मांगों पर विचार करना तो दूर, इनकी आवाजें तक छीन लेने पर अब आमादा है कांग्रेस। इससे अधिक अनैतिक, असंवैधानिक, भर्त्सना लायक कदम किसी सरकार का और क्या हो सकता है भला?''

भाजपा इस विषय पर काफी मुखर और आंदोलित दिख रही है। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता इसके खिलाफ सड़क पर हैं। हजारों ने गिरफ्तारियां दी है। वह सभी सामजिक संगठनों को साथ लेकर इस मुद्दे पर बड़ा आन्दोलन करने की तैयारी में है। बकौल भाजपा प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत कहते हैं– 'यह सवाल केवल राजनीतिक दलों का नहीं है। समाज के

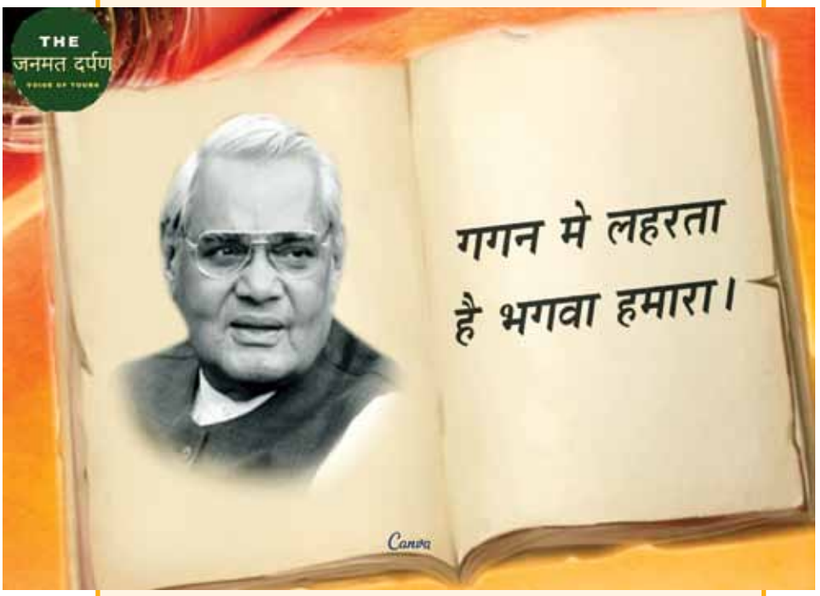

कभी थे अकेले हुए आज इतने
नही तब डरे तो भला अब डरेंगे
विरोधों के सागर में चट्टान है हम
जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे
लिया हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा
कदम बढ रहा है कभी न रुकेगा
न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा
निडर है सभी हम अमर है सभी हम
के सर पर हमारे वरदहस्त करता
गगन में लहरता है भगवा हमारा॥

-अटलजी

सभी वर्गों, संगठनों को सामने आ कर अपनी आज़ादी की रक्षा और लोकतांत्रिक अधिकार की बहाली हेतु साथ आ कर इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए। शासन 15 दिन के भीतर अपना यह काला आदेश वापस ले, अन्यथा पार्टी प्रदेश की जेलों को भरने से लेकर हर तरह का आंदोलन करने और बलिदान देने, सड़क पर उतरने को विवश होगी और इसकी सारी जिम्मेदारी कांग्रेस की होगी।' मुख्य विपक्ष भाजपा ने छत्तीसगढ़ के हर जिले में प्रेस वार्ता आयोजित कर कांग्रेस को यह चेतावनी दी कि 15 मई तक यह काला आदेश वापस लिया जाय। ऐसा नहीं होने पर 16 मई से पार्टी का 'जेल भरो अभियान' शुरू की। इससे संबंधित प्रेस वार्ता को राजनांदगांव में संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. रमन सिंह ने कहा – "राजनीतिक संगठन, सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के संगठन व सामाजिक संगठनों के पास अपनी बात रखने का आंदोलन ही एक मात्र माध्यम होता है। सरकार उसे भी दबाना चाह रही है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाकर राजनीतिक संगठनों के अलावा प्रेस की आजादी भी छीन ली थी। भूपेश बघेल भी इसी रास्ते पर चल रहे हैं। इससे आम लोगों की आवाज दबाई जा रही है।"

कांग्रेसी आपातकाल के खिलाफ पूर्व में भी आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ कर जैसे देश ने जीत हासिल की थी, उसी तरह का यह विषय भी प्रदेश के लोगों के मौलिक अधिकार, उसके जीवन से जुड़ा हुआ है। कांगेस के इस फितूर से एक बार फिर यह साबित हुआ है कि सिविल सोसाइटी को, नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा जागरूक रहना होगा। ऐसा नहीं होने पर कब कांग्रेस जैसी पार्टी अपना लोकतांत्रिक लबादा उतार कर 'इंदिरा सिंड्रोम' का शिकार हो जाय, कहना कठिन है। जब कभी इस अघोषित आपातकाल का मूल्यांकन करेगा तो इस तुगलकी आदेश के खिलाफ भी मुंह नहीं खोलने वाले को इतिहास हंगामा करके बतायेगा कि अभिव्यक्ति की लाज जब लुटी जा रही थी, तब धृतराष्ट्र की सभा में कौरव समाज भी पूरी तरह खामोश ही रहा।●●●

छपते... छपते...

निवेदन

दीप कमल से संबंधित कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो आप नीचे दिए गए पते पर भेज सकते हैं या Watsapp कर सकते हैं. फोन से भी जानकारी दे सकते हैं. ईमेल भी कर सकते हैं. इसके अलावा आपके क्षेत्र में संगठन से संबंधित कोई गतिविधि या पत्रिका में प्रकाशन योग्य कोई समाचार हो, तो उसे भी निम्नलिखित माध्यमों से भेजने का आग्रह है.

कार्यकारी संपादक, दीप कमल, प्रदेश भाजपा कार्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर
डूमरतराई, रायपुर. (छग)
फोन : 0771-2233500
Watsaapp 9425507006.
E mail – jay7feb@gmail.com